राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

Www.gauravshalibharat.com

गौरवशाली भारत

वर्ष : 13 , अंक : 15, पृष्ठ : 08, नई दिल्ली बुधवार 02 अगस्त 2023, मूल्य : 1.50/-

नई दिल्ली से प्रकाशित

RNI No .DELHIN/2011/38334

मुख्य अपडेट

भाजपा जो 13 साल में नहीं कर पाई; वो हमने पांच महीने में किया : केजरीवाल .... पेज 03

जनता की समस्या के समाधान में हीलाहवाली पर होगी सख्त कार्रवाई : सीएम .... पेज 05

मोरक्को के खिलाफ मैच के लिए दिग्विजय भारतीय टीम में, बोपन्ना खेलेंगे अंतिम डेविस कप टाई .... पेज 07

यूपी : तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मृत्यु

बहराइच। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के कोतवाली नानपारा नगर क्षेत्र के कब्रिस्तान में स्थित तालाब में स्नान के दौरान मंगलवार को तीन बालकों की डूबने से मौत हो गयी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि नगर क्षेत्र में शीशम वाला कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में एक तालाब बना हुआ है, जिसमें पानी भरा है। मंगलवार को गर्मी अधिक होने पर नानपारा नगर क्षेत्र के मोहल्ला कहारन टोला निवासी गोलू (08), बादल (07) कुचबंधिया टोला निवासी और अमित (03) स्नान करने के लिए कब्रिस्तान स्थित तालाब में गए। तीनों तालाब के पानी में डूब गए। सभी बालकों की मौत हो गई। कुछ देर बाद परिवार के लोग तलाश करते वहां पहुंचे तो तीनों के शव पानी में पड़ा देखा। घटना की जानकारी मिलने पर तहसीलदार, कोतवाल हेमंत कुमार गौड़, नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल वहीद समेत अन्य पहुंचे हैं। कोतवाल हेमंत कुमार गौड़ ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है तहरीर मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।

देश के 4001 विधायकों की संपत्ति रु 54,000 करोड़

यह राशि तीन राज्यों नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम के वर्ष 2023-24 के संयुक्त सालाना बजट 49,103 करोड़ रुपये से भी ज्यादा

नई दिल्ली। देश के मौजूदा 4001 विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपये है, जो नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 के संयुक्त सालाना बजट से कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) ने चुनाव से पहले विधायकों की ओर से दाखिल हलफनामे से यह आंकड़े जुटाए हैं। रिपोर्ट में बताया कि 4033 विधायकों में से 4001 के हलफनामों का विश्लेषण किया गया। एडीआर की रिपोर्ट से पता चला कि प्रति विधायक औसत संपत्ति 13.63 करोड़ रुपये है। इन 4001 विधायकों में निर्दलीय और 84 राजनीतिक दलों से जुड़े विधायक हैं।

रिपोर्ट में बताया गया, मौजूदा 4001 विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपये है। यह राशि तीन राज्यों नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम के वर्ष 2023-24 के संयुक्त सालाना बजट 49,103 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। वर्ष 2023-24 के लिए नगालैंड का बजट 23,086 करोड़ रुपये, मिजोरम का 14,210 करोड़ रुपये और सिक्किम का बजट 11,807 करोड़ रुपये है।

भाजपा प्रति विधायक औसत संपत्ति 11.97 करोड़ रुपये

बड़े दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 1,356 विधायकों में प्रति विधायक औसत संपत्ति 11.97 करोड़ रुपये, कांग्रेस के 719 विधायकों में प्रति विधायक औसत संपत्ति 21.97 करोड़ रुपये, तृणमूल कांग्रेस के 227 विधायकों में प्रति विधायक औसत संपत्ति 3.51 करोड़ रुपये, आम आदमी पार्टी के 161 विधायकों में प्रति विधायक औसत संपत्ति 10.20 करोड़ रुपये और युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के 146 विधायकों में प्रति विधायक औसत संपत्ति 23.14 करोड़ रुपये पाई गई है।

44 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले

एडीआर की ओर से किए गए एक हालिया विश्लेषण में दावा किया गया कि पूरे भारत में राज्य विधानसभाओं में लगभग 44 प्रतिशत विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एडीआर और एनईडब्ल्यू की ओर से किए गए विश्लेषण में देश भर में राज्य विधानसभाओं और केंद्रशासित प्रदेशों में वर्तमान विधायकों द्वारा चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए शपथपत्रों की पड़ताल की गई और संबंधित विवरण प्राप्त किया गया। विश्लेषण में 28 राज्य विधानसभाओं और दो केंद्रशासित प्रदेशों में 4,033 में से कुल 4,001 विधायकों का विवरण शामिल है।

ठाणे में गर्डर मशीन मजदूरों पर गिरी, 20 लोगो की मौत

तीन लोग घायल, समृद्धि एक्सप्रेसवे पर रात में काम चल रहा था

6 महीने में 88 लोगों गंवाई जान

दिसंबर 2022 में उद्घाटन के बाद से अब तक समृद्धि एक्सप्रेस वे पर 846 हादसे हुए हैं। इनमें से 105 हादसे जानलेवा थे, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सभी हादसों को मिलाकर 660 लोग घायल हुए हैं। इन हादसों में से 87 हादसे गंभीर श्रेणी के थे, जिनमें 232 लोगों को गंभीर चोटें आईं, 215 सामान्य हादसे थे जिनमें 428 लोगों को हल्की चोटें आईं, जबकि 275 हादसे ऐसे थे जिसमें कोई घायल नहीं हुआ।

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार देर रात हादसा हो गया। शाहपुर के पास सरलांबे में हाईवे पर पुल निर्माण के दौरान एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 20 मजदूरों की मौत हो गई। तीन घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही के लिए दो कॉन्ट्रेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। हाईवे पर रात में निर्माण कार्य चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 1: 30 बजे 700 टन वजन वाली गर्डर लॉन्चिंग मशीन और क्रेन करीब 35 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गई। इसके नीचे मजदूर दब गए। साइट पर 28 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से पांच को कोई चोट नहीं आई। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर सारंग कुर्वे ने बताया कि रेस्क्यू का काम सुबह 5: 30 बजे से शुरू कर दिया गया था। दरअसल, गर्डर मशीन का वजन काफी होने से उसे जल्दी से हटाया नहीं जा सका। सुबह करीब 8 बजे क्रेन आने के बाद ही रेस्क्यू काम में तेजी आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहपुर सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 शव लाए गए। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए, और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहां पर स्विट्जरलैंड की कंपनी काम कर रही थी। घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश

सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम-शेम के नारे लगाए

नई दिल्ली। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग-ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक मंगलवार (1 अगस्त) को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और शेम-शेम के नारे लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले- ये बिल संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है।

अमित शाह ने कहा कि संविधान, संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। बिल के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ

राजनीतिक हैं, उनका कोई आधार नहीं है। इस बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल 2023 है। इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया।

बीजेडी-वाईएसआरसीपी का समर्थन

बीजेडी ने दिल्ली सर्विस बिल पर सरकार का समर्थन करने की बात कही है।

राज्यसभा में पार्टी के नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि पार्टी इस बिल पर सरकार के साथ है। वाईएसआरसीपी ने भी इस बिल पर सरकार को समर्थन की बात कही है।

25 जुलाई को इस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसे लेकर आप के राज्यसभा सांसद राघव चड् ?ढा ने कहा कि इससे दिल्ली में लोकतंत्र बाबूशाही में तब्दील हो जाएगा। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीनकर भाजपा के नियुक्त किए गए एलजी को दे दी जाएंगीं।

केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था।

एटीएस ने अलकायदा से जुड़े तीन संदिग्धों को किया गिरफ्तार

राजकोट। गुजरात एटीएस की टीम ने राजकोट से प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर अमन सिराज, शुकुर अली अब्दुल्ला और सैफ नवाज को सोमवार को राजकोट से पकड़ लिया। ये काफी समय से अलकायदा के संपर्क में थे। तीनों संदिग्ध पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और राजकोट के सोनी बाजार में काम करते हैं।

एटीएस ने पकड़े गए लोगों के पास से एक पिस्तौल, 10 कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की संख्या कम हुयी

श्रीनगर। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में आतंकवादियों की संख्या कम हुयी है लेकिन पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है। श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर पुलिस शहीद के 19वें फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के समापन पर मीडियाकर्मियों डीजीपी ने कहा, आतंकवाद पूरी तरह से मिट्टी से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तत्व हैं जो अभी भी जम्मू-कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, सेना का जवान कुलगाम निवासी जावेद अहमद (25) लापता हैं। उनके परिवार को आशंका है कि उनका अपहरण कर लिया गया है। डीजीपी ने कहा, हम उन तत्वों के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठा रहे हैं जो जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली दंगा केस में 6 लोगों पर आरोप तय, 8 धाराओं में केस

दंगे के 3 साल बाद फरवरी में पहली चार्जशीट आई

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को 6 लोगों पर आरोप तय किए है। इन 6 लोगों पर दंगे करने, दुकानों में तोड़फोड़ और फर्नीचर में आग लगाने का आरोप है। इन लोगों पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी थाने में मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे।

एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने राजेंदर झा, तजवीर चौधरी, राजेश झा, गोविंद सिंह, पीतांबर झा, देवेंदर कुमार उर्फ मोनू पंडित के खिलाफ आरोप तय किए है। जांच के बाद 2 फरवरी 2023 कोर्ट में को पहली चार्जशीट दाखिल की गई।

एएसजे पुलस्त्य प्रमाचला ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस बनता है। ये धाराएं 147- दंगा करने, 148- खतरनाक हथियारों से दंगा करने, 149- गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने, 188- किसी अफसर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन, 392- डकैती, 427- आग या विस्फोटक का इस्तेमाल, 436- आग या विस्फोटक पदार्थ से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। मामले की शिकायत अल्का गुप्ता नाम की महिला ने की थी। गुलजार, विकास शर्मा और मोहम्मद इरशाद ने भी ऐसी ही शिकायत की थी। इन तीनों शिकायतों को पहली शिकायत में जोड़ दिया गया। जांच के बाद 22 मार्च 2022 को चार्जशीट आई। चार्जशीट में इन 6 आरोपियों के खिलाफ 8 धाराओं केस दर्ज हुआ। स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर नितिन राय शर्मा दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश हुए । आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए।

नूंह हिंसा में 5 की मौत, 11 एफआईआर दर्ज

133 वाहन फूंके गए; 13 पैरामिलिट्री बटालियन तैनात

नूंह। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा प्रदेश के पुलिस ने जिले को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। नूंह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिल्ट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं।

नूंह हिंसा पर पुलिस ने मंगलवार दोपहर तक कुल 11 स्न्ढ्ढक्र दर्ज कीं। दंगे में 133 वाहनों को फूंका गया। 2 होमगार्ड जवानों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश ष्टरूमनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज ने पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ आपात मीटिंग भी बुला ली है।

एसपी बोले- पुलिस मामले को लेकर गंभीर

नूंह के एसपी का कार्यभार संभाल रहे भिवानी एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने हालातों की जानकारी दी और बताया कि मामले को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वीडियो के आधार पर बाकी सभी की पहचान करके आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

वहीं अब हिंसा नूंह(मेवात) के बाद गुरुग्राम तक फैल गई है, जिसे देखते हुए इन 2 जिलों के अलावा एहतियातन रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत समेत 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूंह में इंटरनेट भी बंद है। नूंह,

फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद हैं। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द है। दरअसल, नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। इससे हिंसा भड़क गई। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस दौरान गुड़गांव के होमगार्ड नीरज और गुरसेवक समेत अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और अन्य घायल हैं।

नूंह में दंगे को लेकर 11 एफआईआर दर्ज

नूंह में सोमवार को हुए दंगों के मामले में पुलिस ने अलग-अलग थानों में 11 स्न्ढ्ढक्रदर्ज की हैं। इसकी जानकारी नूंह पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि इस दंगे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें गुरुग्राम के रहने वाले 2 होमगार्ड नीरज और गुरसेवक के अलावा नूंह के भादस गांव निवासी यात्रा में शामिल शक्ति और एक अन्य की मौत हुई है।

133 वाहनों को भी फूंका गया

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नूंह में हुए दंगों में अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, कुल 133 वाहन उपद्रवियों ने फूंके। इनमें 8 पुलिस के वाहन और 125 यात्रा में शामिल लोगों के वाहन हैं। इसके अलावा भी जानकारी जुटाई जा रही है। दंगे में कुल 23 लोग घायल हुए हैं। इनमें 10 पुलिस के जवान और 13 आम लोगों की जानकारी मिली है।

नूंह में 13 बटालियन तैनात

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पूरे नूंह जिले में पैरामिल्ट्री फोर्स की कुल 14 बटालियन तैनात की गई है। इनमें 7 आरएएफ, 2 बीएसएफ, 2 सीआरपीएफ, 2 आईटीबीपी की बटालियन लगाई गई हैं। दंगे के दौरान कुल 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

ओडिशा ट्रेन हादसा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर को दो चरणों में कुल 162 शव मिले थ

ओडिशा ट्रेन हादसे के 2 महीने बाद भी 29 लाशें लावारिश

बालासोर। ओडिशा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में 294 यात्रियों की मौत हो गई थी। हादसे के दो महीने बाद भी 29 शवों की अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है। एम्स भुवनेश्वर के अधीक्षक, दिलीप परिदा ने कहा कि डीएनए मैच रिपोर्ट का अंतिम बैच इस सप्ताह रिलीज होगा, जिसमें से 2-3 नमूनों के मैच की उम्मीद है। परिदा ने कहा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर को दो चरणों में कुल 162 शव मिले थे, जिनमें से 133 शवों को डीएनए नमूना मिलान के बाद उनके रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा, 29 अज्ञात शवों को एम्स में कंटेनरों में रखा जा रहा है। केंद्र सरकार और ओडिशा सरकार तय करेगी कि उन शवों का क्या किया जाए, जो अंतिम चरण के बाद लावारिस रह जाएंगे। जून की शाम को ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास एक दुखद दुर्घटना में चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली एसएमवीपी-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 294 लोगों की मौत हो गई और 800 से अधिक घायल हो गए। दुर्घटना के कुछ दिनों बाद, आधार कार्ड, ड्राइविंग

लाइसेंस या पैन कार्ड जैसे सत्यापित पहचान प्रमाणों के साथ शवों की पहचान करना काफी आसान था। लेकिन बिना पहचान प्रमाण वाले शवों या एक से अधिक दावेदार वाले शवों के मामले में, डीएनए सैंपलिंग को आधार बनाया गया। एम्स भुवनेश्वर ने शवों को शून्य से कम तापमान में रखने के लिए पारादीप बंदरगाह से कंटेनर-आकार के फ्रीजर का आदेश दिया ताकि किसी भी प्रकार के सड़न को रोका जा सके।

चुनौती भरा है शवों की पहचना करना

कई मामलों में, शवों के साथ पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या अन्य सामान जैसे फोन, बैग या अन्य पहचान योग्य वस्तुएं होती थीं। जबकि इन 29 लाशों से जुड़े कोई पहचान प्रमाण या सामान नहीं मिले।

ऐसे में पीड़ितों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो गया। आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सत्यापित पहचान प्रमाणों के साथ शवों की पहचान का मामला अधिक सीधा था। बिना पहचान प्रमाण वाले शवों के मामले में, पहचान सावधानी से की जानी थी। एम्स के अधिकारियों ने कहा कि डीएनए नमूने की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मौत के बाद नमूने कितनी जल्दी लिए गए थे और क्या वे दाढ़ के दांत जैसे हिस्सों से लिए गए थे।

एक अधिकारी ने कहा, लाशों के सड़ने अवस्था में शवों का डीएनए अनुक्रमण एक समस्या है। चूंकि शव त्रासदी के 30 घंटे से अधिक समय बाद प्राप्त हुए थे, जिनमें से अधिकांश शव डिकंपोज्ड हो चुके थे।

ब्रिगेडियर और ऊपर के अफसर अब एक जैसी वर्दी पहनेंगे

कर्नल और नीचे के रैंक के अफसरों की यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों के लिए मंगलवार (1 अगस्त) से एक जैसी वर्दी कर दी गई है। हाल ही में सेना के कमांडरों ने सम्मेलन में चर्चा के बाद यह फैसला लिया था। यह नियम सभी अफसरों पर लागू होगा चाहे उनका कैडर कुछ भी हो और कभी भी भर्ती (नियुक्ति) हुई हो। वहीं, कर्नल और नीचे की रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सेना के सूत्रों ने बताया कि इस फैसले के तहत सीनियर अधिकारियों की टोपी, कंधे के बैज, गोरगेट पैच (कॉलर पर लगने वाले पैच), बेल्ट और जूते एक जैसे होंगे। वहीं, फ्लैग रैंक के अधिकारी अब बाएं कंधे पर कोई डोरी नहीं पहनेंगे।

यह फैसला रेजीमेंट की सीमाओं से परे, सीनियर लीडरशिप के बीच सेवा मामलों में सामान्य पहचान और नजरिए को बढ़ावा देने के लिए लिया गया।

ये एक निष्पक्ष और न्यायसंगत संगठन होने के लिए भारतीय सेना के चरित्र को और मजबूत करेगा। एक जैसी वर्दी सभी सीनियर रैंक के अधिकारियों को समान पहचान देगी।

द्रौपदी मुर्मू करेंगी अंतरराष्टीय साहित्य उत्सव 'उन्मेष' का भोपाल में उद्घाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के सबसे समावेशी साहित्य उत्सव 'उन्मेष' का उद्घाटन तीन अगस्त को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में करेंगी। साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवासराव ने बताया कि आयोजन 3 से 6 अगस्त के बीच होगा। उन्होंने कहा कि 'उन्मेष' के हर संस्करण में नए विषयों को जोड़ने का प्रयास होता है, ताकि लेखकों के नए समूह को चर्चा में शामिल होने का अवसर मिल सके और उनकी सृजनात्मकता को नई दिशाएँ प्राप्त हो सकें।

शार्ट न्यूज

आरएलडीए ने बंगाल, राजस्थान में एमएफसी के लिए बोलियां की आमंत्रित

कोलकाता। पश्चिम बंगाल और राजस्थान में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने चार मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) के विकास और पट्टे के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। आरएलडीए के एक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रस्तावित भूमि पार्सल संबंधित स्टेशन परिसरों के पास स्थित हैं और रेलवे स्टेशनों के परिसंचरण क्षेत्र का हिस्सा हैं। प्रस्तावित भूमि पार्सल 45 वर्षों की लीज अवधि के लिए हैं। निर्माणकर्ता को अधिकतम 24 महीने की अवधि के भीतर साइटों पर एमएफसी को डिजाइन, वित्त और निर्माण और विकसित करना होगा। सूत्रों ने बताया कि ऑनलाइन प्री-बिड मीटिंग 17 जुलाई, को आयोजित की गई थी और कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के डेवलपर्स ने प्री-बिड मीटिंग में भाग लिया और प्रश्नों का उत्तर दिया। ई-बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2023, 15:00 बजे तक है। एमएफसी रेलवे स्टेशनों के आसपास रेल उपयोगकर्ताओं के लिए शॉपिंग, फूड स्टॉल/रेस्तरां, बुक स्टॉल, एटीएम, दवा और विविध स्टोर, बजट होटल, पार्किंग स्थान और अन्य समान सुविधाएं जैसी कई सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान में भरतपुर, सीकर तथा पश्चिम बंगाल में बांकुरा और कोलकाता के पास दक्षिण 24 परगना में ढाकुरिया में प्रस्तावित है।

छात्रा को पीने के पानी में यूरिन मिलाने के मामले में दर्ज कराई प्राथमिकी

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के मांडल थाने के लुहारिया में छात्रा के पीने के पानी में यूरिन मिलाने एवं आपत्तिजनक पत्र बैग में रखने को लेकर पुलिस ने तीन छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसीपल की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी मुकेश वर्मा ने बताया कि गत 28 जुलाई को स्कूल के इंटरवेल में एक आठवीं कक्षा की छात्रा के पीने के पानी की बोतल में यूरिन भर देने एवं बैग में आपत्तिजनक शब्द लिखा कागज रख दिया था। छात्रा के साथ हुई इस घटना को लेकर स्कूल के प्रिंसीपल वीके जायसवाल ने स्कूल के तीन छात्रों के खिलाफ नामजद मामला मांडल थाने में दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रिंसीपल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच थाना प्रभारी स्वयं कर रहे हैं। प्रिंसीपल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि छात्रा की शिकायत की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रिंसीपल ने शिकायत में बताया कि दो दिन अवकाश होने एवं अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के उपस्थित नहीं होने से आज यह रिपोर्ट पेश की गई है।

नीमराणा में दुकानों में आग लगने से 15 लाख रूपए का नुकसान

अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के नीमराणा कस्बे के कॉम्प्लेक्स में स्थित दो दुकानों में आज आग लगने से करीब 15 लाख रुपए का सामान जल कर राख हो गया। कॉम्प्लेक्स में स्थित हरिओम टेलर की दुकान और महेश गारमेंट्स की दुकान में ये आग लगी। आग लगने के कारणों का अभी कोई पता नहीं।फिर भी शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। पीड़ित दुकान मालिक हरिओम टेलर ने बताया की सुबह साढ़े 6 बजे सफाई कर्मी से सूचना मिली कि कांपलेक्स में आग लग गई है जिसमें आप की दुकान मैं लपटें उठ रही हैं इसके बाद मौके पर जाकर देखा तो मेरी दुकान में सारा सामान जल गया जिसमें करीब 7 मशीनें थी और ग्राहकों का सिला हुआ कपड़ा रखा हुआ था। आग से करीब 7 लाख का सामान मशीन एवं कपड़े जलकर हुआ राख। हरिओम टेलर ने कहा की सूचना देने के लगभग एक घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची।

हरियाणा के नूह में कर्फ्यू के बाद अलवर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट

अलवर। राजस्थान में सीमावर्ती हरियाणा राज्य के नूह में ब्रजमंडल यात्रा में हुए पथराव के बाद इस इलाके में कर्फ्यू लगाने के बाद इससे सट अलवर के नोगावा एवं रामगढ पर पुलिस मुस्तेद है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि शहर के नोगावा थाने से टच करते हुए उनके इलाके की घटना को देखते हुए रामगढ़ सेक्टर में आरएसी की एक कंपनी लगा दी गई है इसके अलावा नौगांवा चेक पोस्ट पर 24 घंटे नाका लगाया गया है। जहां सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा संबंधित थाना प्रभारी और सीओ को अलर्ट किया गया है किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता और प्रतिनिधियों से भी संपर्क बनाए हुए हैं कि कोई भी बात हो तो तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। अभी तक शांति बनी हुई है। फिर भी पूरी तरह पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है।

झारखंड विधानसभा से प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग 2023-24 पारित

रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज दूसरी पाली में सदन ने प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग 2023 -24 और तत् संबंधी विनियोग विधेयक संख्या 03 विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन ने इससे पहले भाजपा के अमर कुमार बाऊरी के कटौती प्रस्ताव को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। चालू वित्तीय वर्ष के लिए पेश कुल 11988 करोड़ रूपये के प्रथम अनुपूरक बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। अनुदान मांग पर हुई चर्चा के बाद सरकार की ओर से जबाब देते हुए वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन बेहतर है और प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई हैं। इसमें कर्मियों के अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलता है। डां. उरांव ने राज्य सरकार की उपलबिध्यों की चर्चा करते हुए कहा कि आज आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चो को पोशाक भी मिल रहा है तथा वृध्दों को भी पेंशन दी जा रही है।

शासकीय कर्मचारियों को कैबिनेट की सौगात

भोपाल। मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद् ने राज्य में 35 साल की सेवाएं पूरी कर चुके शासकीय कर्मचारियों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ देने का निर्णय करते हुए कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के शिवपुर और सीधी जिले के मड़वास में नवीन तहसील खोली जाएगी। राज्य में दूरसंचार अधोसंरचना के कार्यों में तेजी लाने के लिए दूरसंचार विभाग के 2023 के दिशा-निर्देश के मुताबिक प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना में नवीनीकरण की गई मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में 6 नए सरकारी आईटीआई खोले जाने का निर्णय किया गया है। पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में चार नए संकाय शुरू किए जाने को मंजूरी दे दी गई है।

अपरवेदा बांध का गेट हाइड्रोलिक की गड़बड़ी से अचानक खुला,17 गांवों में अलर्ट

खरगोन। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के झिरनिया ब्लॉक के अंतर्गत निर्मित अपर वेदा बांध का गेट आज दोपहर हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी से अचानक खुल जाने के चलते 17 गांवों में अलर्ट जारी करना पड़ा। एनवीडीए के कार्यपालन यंत्री राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि दोपहर अपर वेदा बांध के गेट क्रमांक 3 अचानक हाइड्रोलिक में तकनीकी खामी के चलते यह 2 मीटर खुल गया और तेजी से पानी बहकर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। उन्होंने बताया कि तत्काल जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को घटना की सूचना दी गई और क्षेत्र से लगे 17 गांवों में सायरन बजाकर चेतावनी जारी कराई गयी। एनवीडीए के मुख्यालय बड़वानी, मंडलेश्वर व खंडवा समेत अन्य स्थानों से तकनीकी टीम को बुलाया गया और करीब 4 घंटे में गेट नंबर 2 से प्रेशर डालकर उक्त गेट को बंद करने में सफलता प्राप्त कर ली गई। करीब 4 घंटे गेट खुले रहने के चलते 40 सेंटीमीटर पानी कम होकर 315 मीटर पर आ गया। उन्होंने बताया कि तकनीकी खामी को सुधारा जा रहा है।

असम एसटीएफ ने दो बंगलादेशियों समेत ने छह लोगो को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार लोग कथित तौर पर रोहिंग्या को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कराने के अवैध कारोबार में शामिल थे

एजेंसी

अगरतला। असम पुलिस की विशेष टास्क फोर्स (एसटीफ) ने मानव तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में दो दिन पहले पश्चिम त्रिपुरा के सीमावर्ती गांव मोहनपुर से एक बंगलादेशी नागरिक सहित दो लोगों की गिरफ्तारी के सिलसिले में सोमवार को उत्तरी त्रिपुरा और दक्षिणी त्रिपुरा से दो बंगलादेशियों समेत छह और लोगों को गिरफ्तार किया।

आरोपियों की पहचान उनाकोटी जिले के डालुगांव के उत्तम पाल, पश्चिम त्रिपुरा के कमलघाट के काजल सरकार और सागर सरकार, सिपाहीजला जिले के अब्दुल हुसैन तथा दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया के शिव शंकर घोष और कार्तिक नामा के रूप में की गई।

दो बंगलादेशी नागरिकों की पहचान चांदपुर के सहादत एस के और चटगांव के बिजॉय बरुआ के रूप में की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोग कथित तौर पर रोहिंग्या को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कराने के अवैध कारोबार में शामिल थे। पुलिस ने यहां कहा कि विभिन्न राज्यों में स्थानीय पुलिस के सहयोग से रोहिंग्या से जुड़े लोगों और दलालों के खिलाफ असम सरकार के निर्देशानुसार एसटीएफ ने एक चौतरफा अभियान चलाया है।

सूत्रों ने कहा कि उन पर आईपीसी की धारा 120बी, 121ए, 153 ए, 1बी, 460 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया और असम पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड के तहत ले गई। कुछ दिन पहले सिलचर पुलिस ने बेलोनिया सीमा के रास्ते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 14 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार रोहिंग्याओं ने पार्थ सेन नाम के व्यक्ति का नाम बताया जिसके आधार पर उसे एक पखवाड़े पहले गिरफ्तार किया गया था। बाद में जांच में असम पुलिस को त्रिपुरा के चार और लोगों के नाम मिले जिन्हें अब दो बंगलादेशियों के साथ अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है।

इस मामले के सिलसिले में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) और पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में एसटीएफ की पांच टीमों ने त्रिपुरा के विभिन्न सीमावर्ती जिलों का दौरा किया।

कश्मीर में एनजीओ आतंकवादी वित्तपोषित मामले को लेकर छापेमारी

श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) आतंकवादी वित्तपोषित मामले में मंगलवार को कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवाद रोधी एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में नौ स्थानों पर छापे मारे। उनकी टीम ने पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की मदद से छापेमारी की। जिसमें और अधिक जानकारियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मामला एनजीओ और ट्रस्टों द्वारा जम्मू-कश्मीर में धर्मार्थ गतिविधियों के लिए दिए गए धन को 'अलगाववादी गतिविधियों' में लगाने से संबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने के बाद, यह मामला आठ अक्टूबर, 2020 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में पाया गया कि कुछ एनजीओ और ट्रस्ट इसके माध्यम से घरेलू तथा विदेश में धन एकत्र कर रहे हैं। इस धन का उपयोग जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।

अधिकारियों ने बताया,इनमें से कुछ एनजीओ के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) आदि से संबंध हैं। इसके अलावा, ऐसे एनजीओ, ट्रस्ट और सोसायटी द्वारा एकत्र किए गए धन को जम्मू-कश्मीर भेजा जाता है। इन एनजीओ अच्छाई की आड़ में छिपकर घाटी में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बनाए रखने में मदद करते है, जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता तथा सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

हिमाचल को सेतु भारतम परियोजना में 400 करोड़ मिलेंगे : गडकरी

एजेंसी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मंगलवार को आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल के फोरलेन, राष्ट्रीय राजमार्ग और तटीकरण के लिए 400 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।

गडकरी ने कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सेतु भारतम परियोजना, सीआरएफ के तहत 400 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ रुपये पहले ही दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फोरलेन व एनएच को जो भी नुकसान हुआ है, उसकी मरम्मत के लिए जितना पैसा लगेगा, खर्च किया जाएगा।

गडकरी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश एवं भू-स्खलन से सड़कों, पुलों और अन्य सम्पदा का भारी नुकसान हुआ है तथा आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रभावितों को हरसम्भव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि यहां लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है जो कि उनकी कल्पना से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि मरम्मत एवं बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करने के दृष्टिगत केंद्र सरकार की ओर से सीआरआईएफ के अंतर्गत 400 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के आस-पास एक किलोमीटर तक सम्पर्क मार्गों की मरम्मत का व्यय भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वहन करेगा।

एजेकेपीसी ने प्रदेश में एक साथ त्रिस्तरीय पीआरआई चुनाव की मांग की

श्रीनगर। ऑल जम्मू-कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस (एजेकेपीसी) ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर केंद्र शासित प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) के लिए एक साथ चुनाव कराने की मांग की। एजेकेपीसी प्रतिनिधिमंडल ने कहा, पहले जम्मू-कश्मीर में पीआरआई के लिए चरणबद्ध तरीके से चुनाव होते थे, जिसमें काफी समय लगता था। उन्होंने कहा,हम मांग करते हैं कि इस बार केंद्र शासित प्रदेश में त्रिस्तरीय पीआरआई चुनाव एक साथ होने चाहिए। एजेकेपीसी के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि समय बचाने के लिए ग्राम स्तर पर ब्लॉक विकास और जिला योजना तथा विकास बोर्ड के चुनाव हलका पंचायत चुनावों के साथ-साथ कराए जाने चाहिए।

केसीआर ने हैदराबाद में 466 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने मंगलवार को यहां नेकलेस रोड पर 466 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

बेड़े में अब 108 आपातकालीन सेवाओं के लिए 204 एम्बुलेंस, अम्मावाडी माँ और बच्चे की देखभाल कार्यक्रम के लिए 288 और शवगृह एम्बुलेंस के लिए 34 एम्बुलेंस शामिल हैं।

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने स्वास्थ्य विभाग में 466 नए वाहन शुरू करने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने एम्बुलेंस उपलब्धता में महत्वपूर्ण सुधार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब राज्य का गठन हुआ था तब प्रत्येक एक लाख लोगों के लिए

केवल एक एम्बुलेंस थी, अब यह अनुपात बढ़कर प्रत्येक 75 हजार व्यक्तियों के लिए एक 108 वाहन हो गया है। मंत्री हरीश राव ने इन एम्बुलेंस के लिए आवश्यक धन हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर को श्रेय दिया।

उन्होंने जन्म से मृत्यु तक राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यापक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग में पांच स्तरीय प्रणाली की स्थापना की सराहना की, जिसने नीति आयोग से मान्यता प्राप्त की है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कल्याणकारी योजनाएं महज चुनावी हथकंडे नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के वास्तविक प्रयास हैं।

त्रिपुरा में नौकरी पाने की चाह रखने वाले उप्र-बिहार के पांच युवक गिरफ्तार

एजेंसी

अगरतला। त्रिपुरा पुलिस ने उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इन लोगों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के त्रिपुरा सीमावर्ती मुख्यालय में साक्षात्कार के दौरान राज्य के स्थायी आवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) प्रस्तुत करने के मामले में गिरफ्तार किया है।

आरोप में शीर्ष स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमान में बाहरी लोगों ने त्रिपुरा आरक्षण के तहत नौकरी पाने के लिए पीआरसी हासिल किया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), कांग्रेस और तिपरा मोठा ने मंगलवार को बाहरी लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी और राज्य सरकार से सभी तरह की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की हितों की रक्षा करने की मांग की।

विपक्षी पार्टियों और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन राज्य प्रशासन ने इन मांगों की अनदेखी कर दी थी। पिछले सप्ताह स्थानीय लोगों ने एक बाहरी व्यक्ति को नौकरी पाने के लिए फर्जी पीआरसी के साथ कैपिटल कम्प्लेक्स इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि प्रत्येक दिन बड़े पैमाने पर त्रिपुरा के बाहर के बेरोजगार युवक राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के जरिए त्रिपुरा आरक्षण के तहत केंद्रीय सुरक्षा बलों में नौकरी पाने के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि बीएसएफ शलबगमगन परिसर में एसएससी-जीडी के लिए आयोजित साक्षात्कार के दौरान त्रिपुरा के बेरोजगार युवकों ने बिहार के तीन और उत्तर प्रदेश के दो युवकों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवके पास विभिन्न एसडीएम दफ्तर रिश्वत के जरिए हासिल किया गया असली पीआरटीसी था।

बारामूला जिले में ड्रग तस्कर का निर्माणाधीन घर कुर्क

श्रीनगर । जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर के निर्माणाधीन घर को कुर्क करने के साथ ही एक अन्य व्यक्ति का वाहन जब्त कर लिया है। आधिकारिक सूत्रो ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत 27 जून को बारामूला पुलिस ने सक्षम अधिकारियों से कानूनी मंजूरी प्राप्त करने के बाद ड्रग तस्का बरकत अली मेन के मुख्य मोहल्ला पट्टन में 10 मरला भूमि पर एक निर्माणाधीन घर को कुर्क कर लिया। वहीं पुलिस ने कलंत्रा पाईन के अब्दुल रहमान मलिक का वाहन भी जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि जांच से साबित हुआ है कि उक्त चल/अचल संपत्ति ड्रग तस्करों द्वारा अवैध तस्करी से जुटायी गयी थी।

प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी आपदा प्रथम बार देखी: सुक्खू

शिमला। हिमसचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी आपदा प्रथम बार देखी गई है जिसने राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

सुक्खू ने कुल्लू जिला में सर्वाधिक प्रभावित बड़ा भुईन, देवधार, शिरड़, कलाथ और आलू ग्राउंड मनाली का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों से संवाद किया और इस चुनौतीपूर्ण समय में उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत केंद्र से इस आपदा से उबरने में हिमाचल को उदार सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गत माह सात से 11 जुलाई के मध्य हुई भारी बारिश से प्रदेश में सम्पति के साथ-साथ सड़कों और पुलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में परिवहन के अन्य साधन सीमित हैं और ऐसे में सड़कें राज्य की जीवन रेखा मानी गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल दौरे का उनका आग्रह तुरंत स्वीकार किया है जिसके लिए वह उनके आभारी हैं।

निलंबित सभापति गुप्ता चार्ज लेने दूसरे दिन भी पहुंची कार्यालय

अलवर। राजस्थान के अलवर नगर परिषद में निलंबित सभापति बीना गुप्ता आज दूसरे दिन भी कार्यालय पहुंची जहां तालाबंद होने पर बाहर ही कुर्सी पर बैठ गई। निलंबित सभापति गुप्ता आज दूसरे दिन भी हाईकोर्ट के 26 मई को दिए आदेशों को लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंची। वह सभापति कार्यालय के बाहर कुर्सी पर बैठी रही। नगर परिषद पहुंची। निलंबित सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि उन्हें एसीबी की ओर से रिश्वत प्रकरण में ट्रेप करने और पूर्व आयुक्त एवं अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी से जुड़े दोनों ही मामले में निलंबन के डीएलबी ने आदेश जारी किए थे। जिसके बाद उन्हें बर्खास्त किया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले में बीना गुप्ता को पार्षद एवं सभापति पद से बर्खास्त करने का आदेश खारिज किया है। वह पूर्व एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी से मारपीट का है। उन्होंने बताया कि सरकार ने दोनों मामलों में बर्खास्त किए थे और हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों मामले क्रैश हो गए और वर्दी कर दिया और इस संबंध में न्यायिक जांच भी पूरी हो चुकी है जिसको 70 दिन हो चुके हैं।

भाजपा ने सचिवालय का घेराव कर किया प्रदर्शन

जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार एवं कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस सरकार के खिलाफ सचिवालय का घेराव कर प्रदर्शन किया।

बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता घेराव के दौरान पुलिस द्वारा लगाये गये अवरोधक को पार करते हुए आगे बढ़े और तीसरे एवं आखिरी अवरोधक पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही इन लोगों की भीड़ को पुलिस ने रोक लिया । इसके बाद कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हो गए और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे

कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीछे धकेलने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारे छोड़नी पड़ी। पुलिस ने दो बार पानी की बौछारे छोड़ी और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष डा सतीश पूनियां, सांसद मनोज राजोरिया सहित भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को चोंटे आई और श्री राजोरिया सहित कुछ कार्यकर्ताओं को सवाई मान सिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़, डा पूनियां, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, सांसद बालकनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा अरुण चतुर्वेदी, विधायक वासुदेव देवनानी सहित कई नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। इससे पहले प्रदर्शन के दौरान श्री जोशी सहित अन्य नेता सड़क पर बैठ गए और मीडिया से बात की और श्री जोशी ने बहुचर्चित लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है जो अपने मंत्री को रातों रात हटा दिया गया।

नीतीश सरकार को उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत

एजेंसी

पटना। बिहार सरकार को आज पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई और अब नीतीश सरकार जातीय गणना का काम पूरा करा सकेगी ।

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खण्डपीठ ने मंगलवार को जातीय गणना पर रोक लगाने के आग्रह से संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया ।इस मामले पर 17 अप्रैल को पहली बार

सुनवाई हुई थी। उच्च न्यायालय ने चार मई को जाति आधारित गणना पर रोक लगाते हुए उस समय तक हुए सर्वे में प्राप्त आंकड़ों को नष्ट नहीं करने का आदेश दिया था और सुनवाई की अगली तिथि तीन जुलाई तय की थी । इस मामले में लगातार दोनों पक्षों को सुनने के बाद 7 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दिया गया था कि राज्य सरकार सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना करा रही है जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सरकार ने इस गणना का उद्देश्य नहीं बताया है, जिससे इन संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है । यह जनता के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा । राज्य सरकार ने आकस्मिक निधि से 500 करोड़ इस सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किया है, जो जनता के धन का दुरुपयोग है। संविधान राज्य सरकार को इस तरह का सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं देता है।

वहीं, राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यह राज्य का नीतिगत निर्णय है और इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। ऐसी कोई जानकारी सरकार नहीं मांग रही है जिससे निजता के अधिकार का हनन होगा।

शिमला में रैली, प्रदर्शन और शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध

शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला के जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने मंगलवार को बताया कि मॉल रोड शिमला पर रैली, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

नेगी ने कहा कि चिन्हित क्षेत्रों रिज मैदान से छोटा शिमला-कनेडी हाउस, रेन्डवज रेस्तरां से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में, सकेनडल पवाइंट से काली बाडी मंदिर, लिंक रोड छोटा शिमला गुरूद्वारा से छोटा शिमला-कसुमपटी सड़क, छोटा शिमला चौक-राजभवन से ओक ओवर, लिंक रोड कार्ट रोड से मजिठा हाउस, एजी आफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्लयूडी आफिस से चौडा मैदान और जिलाधीश कार्यालय से 50 मीटर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर ये आदेश तत्काल प्रभाव से दो महीने के लिए लागू होंगे।

शार्ट न्यूज

आर्चिड सोसाइटी ने जीती बास्केटबॉल प्रतियोगिता

गाजियाबाद/नोएडा। नोएडा में ड्रीम बास्केटबॉल एकेडमी के बैनर तले दो दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें जेएम आर्चिड सोसाइटी ने पहला स्थान प्राप्त किया। इससे पहले प्रतियोगिता का उदघाटन प्रधानाचार्य अपर्ना मैगी ने किया। प्रतियोगिता में करीब 150 से 200 बच्चे शामिल हुए। जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहीम बावा, तकनीकि डायरेक्टर सुनील त्यागी, कोच अमित मिश्रा, दिल्ली इनकम टैक्स के कोच अशोक शर्मा, एकेडमी फाउंडर गगन बैसोया, कोच यश शर्मा, रिद्धम बिधुड़ी, मोहित नागर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। गाजियाबाद के नंदग्राम स्थित फातिमा किंडर गार्डन स्कूल की छात्रा आरना ने डांस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। स्कूल स्तर पर हुई प्रतियोगिता में नर्सरी कक्षा की 50 से अधिक छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। स्कूल शिक्षिका अंजू भाकुनी ने बताया कि फाइनल प्रतियोगिता में आरना शिशोदिया ने बॉलीवुड गाने पर डांस कर सभी का मन मोह लिया था। इसी के साथ आरना सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल परिसर में विजेता आरना और अन्य उपविजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। स्कूल प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतकर आरना ने दादा बालकिशन, दादी संतोष देवी समेत परिवार का नाम रोशन किया है।

अंतरराज्यीय चोर गैंग के दो सदस्य पकड़े

गौतम बुद्ध नगर। नोएडा के थाना 39 पुलिस ने अंतरराज्यीय चोरों के गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जो चोरी की वारदात करते समय अच्छे कपड़े पहनते थे और अपने साथ अपनी पत्नी को भी रखते थे। जिससे कि कोई उन पर शक ना करे। इन चोरों के कब्जे से पुलिस ने 7 तोला सोना, वारदात को अंजाम देते समय इस्तेमाल होने वाली स्कूटी, ताला तोड़ने के औजार और तमंचा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने जिन दोनों चोरों को पकड़ा है उनमें शातिर चोर शहजाद पटियाला पंजाब का रहने वाला है। सिराजुद्दीन कोलकाता का निवासी है। इन दोनों को थाना 39 पुलिस ने सेक्टर 37 स्थित शौचालय के पास से गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि यह दोनों सूटेड बूटेड होकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए निकलते थे। इनके साथ इनकी पत्नी भी शामिल होती थीं। यह पहले स्कूटी में बैठकर मकानों की रेकी किया करते थे। रेकी के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इन लोगों ने 6 जुलाई को सेक्टर 37 में एक मकान का ताला तोड़कर जेवरात चुराए थे। इसके बाद से ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इनकी पहचान कर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी।

गाजियाबाद नगर निगम ने सुनी जनसमस्याएं

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम के मुख्य कार्यालय में में मंगलवार को संभव जनसुनवाई कार्यक्रम हुआ। इसमें 15 लोगों की शिकायतें प्राप्त हुईं, जो निर्माण, उद्यान, स्वास्थ्य, जलकल और संपत्तिवि विभाग से संबंधित थीं। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने मौके पर ही संबंधित विभागों को ये समस्याएं निपटाने का निर्देश दिया। अपर नगरायुक्त अरुण कुमार यादव ने बताया, जनसुनवाई संभव में आए हुए आगंतुकों से उनकी समस्याओं को समझा गया। नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए। ग्राम घूकना, नंदग्राम, लोहिया नगर, विजयनगर, पटेलनगर, कविनगर से शिकायतकर्ता आए। जिनकी समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल कार्रवाई कराई गई। कई पार्षदों द्वारा भी अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसके क्रम में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उन्हें निपटाने के लिए कहा गया। गाजियाबाद नगर निगम की महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने जनसुनवाई कार्यक्रम में आई शिकायतों और उसके निस्तारण की रिपोर्ट अपर नगरायुक्त से मांगी है।

ड्रग तस्करी रोकने को हुआ मंथन

गाजियाबाद5। गाजियाबाद में मादक पदार्थों (नारकोटिक्स) की बिक्री व तस्करी रोकने के लिए एक अहम बैठक कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में हुई। इसमें यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर कड़ी चौकसी बरतने और नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, खरीद-फरोख्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को तेज करने की जरूरत है। जनपद में सतर्कता और इंटेलिजेंस को बेहतर करना होगा। यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को अपने मुखबिर तंत्र से समन्वय स्थापित कर और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है। डीएम ने निर्देशित किया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसे स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्रों में रहने वाले लोगों का वैरिफिकेशन करने का निर्देश दिया है।

दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एनएचपीसी और एलिम्को के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

एनएचपीसी की सीएसआर पहल के तहत एनएचपीसी लिमिटेड और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) के बीच 1 अगस्त 2023 को एनएचपीसी निगम मुख्यालय, फरीदाबाद में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। श्री उत्तम लाल, निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी की गरिमामयी उपस्थिति में समूह उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) - सीएसआर एवं एसडी, एनएचपीसी तथा महाप्रबंधक (विपणन), एलिम्को द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के तहत, एनएचपीसी उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित एनएचपीसी परियोजनाओं के आस-पास के लगभग 1000 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण के लिए सीएसआर के अंतर्गत सहायता प्रदान करेगा। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (सीएसआर एवं एसडी), एनएचपीसी तथा एनएचपीसी, सीएसआर एवं एसडी विभाग और एलिम्को के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

गाजियाबाद के हॉस्पिटल में लगी आग

गाजियाबाद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सोमवार देर रात एक हॉस्पिटल के बाहरी हिस्से में आग लग गई। धुआं भरने की वजह से करीब 10 मरीजों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। फायर फाइटर्स ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया, रात करीब 1 बजकर 51 मिनट पर सूचना मिली कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में न्याय खंड स्थित एमीकेयर हॉस्पिटल में लाग लग गई है। तुरंत दो फायर टेंडर रवाना किए गए। घटनास्थल पर जाकर देखा तो हॉस्पिटल के बाहर बिजली के पैनल में आग लगी हुई थी। इससे पूरे हॉस्पिटल में धुआं भर गया था। हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ के साथ फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 10 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद पानी की बौछार करके आग पर काबू पाया गया।

भाजपा जो 13 साल में नहीं कर पाई; वो हमने पांच महीने में किया : केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर दावा किया कि नगर निगम में उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से स्थितियों में काफी बदलाव हुआ है।

उनका दावा है कि भाजपा जिन कामों को वर्षों में नहीं कर सकी वह उन्होंने कुछ माह में कर दिखाया है। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रतिकिया नहीं आई है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट में लिखा, जो काम भाजपा 13 साल में नहीं कर पाई, वो काम हमने सिर्फ पांच महीने में कर दिखाया। 2010 के बाद आज पहली बार नगर निगम में कमिश्नर से लेकर चपरासी तक, सफाई कर्मचारी से लेकर शिक्षक तक, माली से लेकर डीबीसी कर्मचारी तक सभी को महीने की पहली तारीख को वेतन मिल रहा है और ये सब इसलिए हो पाया, क्योंकि अब निगम में भी आप की ईमानदार सरकार है।

सीएम केजरीवाल ने खुशी जाहिर करते हुए आगे कहा कि निगम के सभी कर्मचारियों से आज मेरी एक अपील है। मेरी तरफ से बच्चों और माता-पिताजी के लिए घर मिठाई जरूर लेकर जाना।

नूंह हिंसा पर सीएम केजरीवाल की शांति और भाईचारे की अपील, बोले- ये अच्छे संकेत नहीं

हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद कई इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी घटना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान जारी किया है। उन्होंने अपने ट्विट हैंडल से ट्वीट करते हुए हिंसा प्रभावित इलाकों के लोगों से शांति और भाईचारे की अपील की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर नूंह हिंसा को लेकर कहा कि नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा बहुत परेशान करने वाली है। मणिपुर के बाद हरिणाया में इस तरह की हिंसा का संकेत अच्छा नहीं है। मैं हरियाणा की समस्त जनता से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। ऐसे नाजुक वक्त में हम शांति और आपसी भाईचार कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सभी को मिलकर काम करना होगा। हरियाणा के नूंह (मेवात) में सांप्रदायिक हिंसा बेहद परेशान करने वाली है। पूर्वोत्तर में मणिपुर के बाद अब हरियाणा में इस तरह की वारदात अच्छे संकेत नहीं हैं। हरियाणा की समस्त जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नाजुक समय में हम शांति और आपसी भाईचार कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों और हिंसा की सियासत को हम सभी को मिल-जुलकर हराना है।

नूंह में बवाल के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट

नई दिल्ली। हरियाणा के नूंह में दो गुटों के बीच हुए बवाल के बाद दिल्ली में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी थानाध्यक्षों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इलाके में गश्त करने व सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। थानाध्यक्षों समेत सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी को रात में थाने में रुकने क आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा बरती जा रही हैं। इन इलाकों में अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नूंह बवाल के बाद दिल्ली में सोमवार देर हाईअलर्ट जारी कर दिया गया। सभी थानाध्यक्षों को कहा गया है कि वह इलाके में स्टाफ के साथ पूरी तरह गश्त करेंगे। ये भी आदेश दिया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी रात के समय घर नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों को इलाके के धार्मिक गुरुओं से बात करने के लिए कहा है। नांगलोई में हुए पथराव के बाद दिल्ली का माहौल पहले ही तनावपूर्ण बना हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि नूंह में मेवात दर्शन शोभायात्रा में झगड़ा हो गया है। गोली चलने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि नूंह शहीदी पार्क के पास झगड़ा हुआ है। अभी यह पता नहीं लग पाया किस किसके बीच में झगड़ हुआ है। इलाके में भारी तनाव है। दोनों तरफ से पथराव जारी है। कई वाहन फूंकेने की खबर है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं। वहां की हवाई फायर भी हुए हैं। नूह का बाजार बंद हो गया है। नूंह में धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है।

पॉक्सो केस में बृजभूषण को राहत

नाबालिग ने क्लोजर रिपोर्ट का नहीं किया विरोध

एजेंसी

नई दिल्ली। अदालत ने कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने की दिल्ली पुलिस की सिफारिश को स्वीकार किया जाए या नहीं इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

छह सितंबर को होगी सुरक्षित फैसले पर सुनवाई

नाबालिग का बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसका फैसला 6 सितंबर को सुनाया जाएगा। पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम का मामला एक नाबालिग पहलवान और उसके पिता की अब वापस ली गई शिकायत पर आधारित है।

बृजभूषण सिंह को पॉक्सो मामले में मिली राहत

15 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक सिंह के खिलाफ पॉस्को अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कोई पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिला।

पुलिस को नहीं मिली कोई पॉक्सो के तहत सबूत

अदालत में दायर की गई पुलिस की 552 पन्नों की रद्दीकरण रिपोर्ट में एक नाबालिग पहलवान, उसके पिता, सिंह और अन्य गवाहों के बयानों का हवाला दिया गया है। रद्दीकरण रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है जब कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है।

आईआईएमसी में एडमिशन के लिए ई-काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू

11 अगस्त को आएगी पहली मेरिट लिस्ट, 4 सितंबर से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र

नई दिल्ली, 1 अगस्त। देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) में पांच पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ई-काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। ई-काउंसलिंग के लिए विद्यार्थी https://iimc.admissions.nic.in/ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को 1,500 रुपये और अन्य श्रेणी के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आयोजित इस प्रक्रिया में पहली मेरिट लिस्ट 11 अगस्त को घोषित की जाएगी। विद्यार्थियों को सीट अलॉटमेंट के पश्चात ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा।

आईआईएमसी के प्रवेश प्रभारी प्रो. (डॉ.) राकेश गोस्वामी ने बताया पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी पीजी) 2023 के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। अंग्रेजी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में पीजी डिप्लोमा में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ई-काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। 4 सितंबर, 2023 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा।

प्रो. गोस्वामी ने बताया कि आईआईएमसी में प्रवेश के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का जन्म 1 अगस्त 1998 को या उसके बाद (1 अगस्त, 2023 को अधिकतम 25 वर्ष) होना चाहिए।

ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जन्म तिथि 1 अगस्त 1995 या उसके बाद (1 अगस्त 2023 को अधिकतम 28 वर्ष) की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जन्म तिथि 1 अगस्त 1993 या उसके बाद (1 अगस्त, 2023 को अधिकतम 30 वर्ष) की होनी चाहिए।

डीयू ने की सीएसएएस के पहले राउंड की घोषणा

पहले दौर में ही घोषित किए कुल 85853 आवंटन

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) - यूजी-2023 के तहत स्नातक प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए पहले एलोकेशन राउंड की घोषणा कर दी है। इस आवंटन में प्रोफ़ोर्मेंस अथवा प्रेटिक्ल वाले प्रोग्रामों को छोड़ कर बाकी सभी प्रोग्रामों के लिए सभी कॉलेजों हेतु सीटों का आवंटन किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की डीन एडमिशन प्रो. हनीत गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले राउंड में 202416 योग्य उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर प्रोग्राम और कॉलेज संयोजन के आवंटन पर विचार किया गया था। पहले सीएसएएस दौर में ही कुल 85853 आवंटन घोषित किए गए हैं। इसमें यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस और दो अतिरिक्त कोटा, पीडब्ल्यूबीडी और कश्मीरी प्रवासियों के सभी कॉलेजों में सभी कार्यक्रमों के लिए आवंटन शामिल है।

प्रो. गांधी ने बताया कि 7042 उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता मिली है। लगभग 22000 उम्मीदवारों को उनकी पहली पांच प्राथमिकताओं में से एक सीट आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीट मिल गई है, उन्हें शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 को शाम 04: 59 बजे तक सीट स्वीकार करनी होगी। कॉलेजों में आवंटित उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच कॉलेज स्वयं करेंगे। शनिवार, 5 अगस्त, 2023 को शाम 04: 59 बजे तक कॉलेज आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे। जिन उम्मीदवारों के आवेदन कॉलेज द्वारा अनुमोदित हो जाते हैं उन्हें रविवार, 6 अगस्त, 2023 को शाम 04: 59 बजे तक फीस जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवारों की ओर से कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो कॉलेज मांग सकते हैं।

प्रो. गांधी ने बताया कि जिन उम्मीदवारों को पहले दौर में सीट एलोकेट की गई है, उन्हें निर्धारित समय तक प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। केवल वही उम्मीदवार दूसरे राउंड में भाग लेने के लिए अपग्रेड का विकल्प चुन सकेंगे जो फीस भुगतान सहित अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। प्रो. गांधी ने उम्मीदवारों को सलाह दी कि सभी अपडेट और शेड्यूल के लिए अपने डैशबोर्ड और विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट की नियमित जांच करते रहें।

प्रो. गांधी ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा दूसरे राउंड की घोषणा गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को शाम 05: 00 की जाएगी।

अज्ञात बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को मारी गोली, मौत

गौतम बुद्ध नगर। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में रविवार रात को एक सब्जी विक्रेता को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद सब्जी विक्रेता घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सोमवार शाम को इलाज के दौरान सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।

दरअसल मूलरूप से बदायूं का रहने वाला कोमिल (50) ग्रेटर नोएडा में सब्जी बेचने का कार्य करता था। रविवार रात को वह सब्जी बेचकर सुपरटेक की तरफ जुगाड़ के मोटरसाइकिल रिक्शा से वापस जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ अज्ञात बदमाश आए और उन्होंने कोमिल पर फायरिंग कर दी, इस फायरिंग के दौरान वह घायल हो गया। जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तत्काल आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आनन-फानन में सब्जी विक्रेता को गम्भीर हालात में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और हमलावरों की तलाश में जुट गई।

सब्जी विक्रेता कोमिल को जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार शाम को सब्जी विक्रेता कोमिल की इलाज के दौरान मौत हो गई।

ग्रेटर नोएडा में किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल सीईओ से मिला

गौतम बुद्ध नगर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसान सभा के नेतृत्व में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसान 75 दिनों से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने आज सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर बात बनती हुई नजर आई। किसानों के कई अहम मुद्दों को सीईओ ने बोर्ड बैठक में बेगाने की सहमति दी है।

धरना दे रहे किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल सीईओ रवि कुमार एनजी से मिला। किसानों ने बताया कि प्राधिकरण की तरफ से प्राधिकरण स्तर के मुद्दों को जिनमें 17.5 परसेंट प्लॉट कोटा, 120 वर्ग मीटर के न्यूनतम साइज को पुन: बहाल करने, किसान कोटा के प्लॉटों पर पैनाल्टी के प्रावधान को समाप्त करने एवं आबादी निस्तारण के मसलों को आगामी बोर्ड बैठक में ले जाने पर सहमति व्यक्त की।

533 और 208 एसआईटी प्रकरणों को शासन स्तर से जल्द ही अनुमोदित कराने का आश्वासन दिया। नए कानून के अनुसार प्रभावित परिवारों को कवर करने, रोजगार ,भूमिहीनो के प्लाट, और सबसे प्रमुख मुद्दे 10 प्रतिशत प्लाट पर और समय देने को कहा है । किसानों और प्राधिकरण के सीईओ के बीच बातचीत सकारात्मक रही।

किसान सभा के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने बातचीत के संबंध में धरना स्थल पर मौजूद किसानों को अवगत कराते हुए कहा कि प्राधिकरण स्तर के मुद्दों पर आगामी बोर्ड बैठक में कार्रवाई का आश्वासन मिला है, बाकी चार बड़े मुद्दों पर प्राधिकरण ने और समय मांगा है ,10 प्रतिशत प्लाट के संबंध में कितनी जमीन की आवश्यकता होगी।

गला रेतकर युवक की हत्या, सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान

नई दिल्ली। सदर बाजार में सोमवार आधी रात को मोहम्मद समीर (30) की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच के बा द समीर के शव को सब्जी मंडी मोर्चरी भेज दिया। हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी की पड़ताल हुई तो आरोपी फुटेज में कैद मिले। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रिजवान की पहचान की। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल हत्या के सही कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि समीर का पत्नी से विवाद था। वह पत्नी के चरित्र पर शक करता था। हत्या से पूर्व समीर दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इस दौरान झगड़े में वारदात को अंजाम दिया गया।

दिल्ली-6 बिजनेस कॉन्क्लेव में वॉल्ड सिटी के व्यापारियों ने एमएसएमई की स्कीम को समझा

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा करोल बाग में आयोजित दिल्ली-6 बिजनेस कॉन्क्लेव में वॉल्ड सिटी के व्यापारियों ने एमएसएमई की स्कीम को समझा। कॉन्क्लेव में पुरानी दिल्ली के 200 से अधिक ट्रेडर्स और अलग-अलग मार्केट असोसिएशंस के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मंडल के महामंत्री हेमंत गुप्ता ने बताया कि कॉन्क्लेव में एमएसएमई के सीनियर ऑफिसर डॉ. आरके भारती, सुनील कुमार और बृजेश कुमार ने मंत्रालय की योजनाओं को विस्तार से बताया। खुदरा और थोक व्यापारी भी अब एमएसएमई को मिलने वाले सभी लाभ ले सकेंगे। सरकार ने खुदरा व थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का दर्जा दे दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के तहत प्राथमिकता के आधार पर व्यापारी बैंकों से कर्ज हासिल कर सकते हैं। खुदरा व थोक व्यापारी उद्यम पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। खुदरा और थोक व्यापारी भी गारंटी मुक्त लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। एमएसएमई का दर्जा मिलने से खुदरा व थोक व्यापारी अब सरकारी पोर्टल जेम पर उत्पादों की बिक्री भी कर सकते हैं। वो भी बिजनेस टु बिजनेस (बीटुबी) रूप में उत्पाद बेच सकते हैं। कार्यक्रम में मुकेश सचदेवा, श्रीभगवान बंसल, राजेंद्र शर्मा जैसे व्यापारी नेताओं ने अपनी आशंकाएं और सवाल भी अधिकारियों के समक्ष रखे। कॉन्क्लेव में बलदेव गुप्ता, प्रदीप गुप्ता , नंद किशोर बंसल, चंद्रभूषण गुप्ता, ललित अग्रवाल, प्रकाश बैराठी, मैकी जैन, विवेक कौशिक , पंकज शर्मा, राकेश यादव, विनय नारंग, अजय शर्मा, महेश सिंघल, परमजीत सिंह पम्मा, निरंजन पोद्दार और यूनिटी ग्रुप के डायरेक्टर नरेश अग्रवाल मौजूद रहे।

जनवरी में होगा 'दिल्ली-6' एक्सपो

हेमंत ने बताया कि जनवरी में प्रगति मैदान में दिल्ली-6 एक्सपो का प्लान किया जा रहा है। इसमें व्यापारी और फैक्ट्री मालिक अपने स्टॉल लगाकर प्रोडक्ट्स दिखा सकेंगे। व्यापारियों को अपना ब्रैंड प्रमोट करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली समेत दूसरे शहरों के व्यापारियों को आमंत्रित किया जाएगा। एक जगह दिल्ली-6 के बिजनेस को समझने का अवसर मिलेगा।

दिल्ली संशोधन विधेयक का समर्थन करेगा बीजद

एजेंसी

नयी दिल्ली। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्ववाली बीजू जनता दल (बीजद) 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2023' को पारित करने का समर्थन करेगा और विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में बीजद के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने और उपरोक्त कार्य करने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया है।

गौरतलब है कि विपक्ष के भारी विरोध के बीच सरकार ने बहुचर्चित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2023' को सदन में चर्चा तथा पारित कराने के लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किया।

विधेयक में दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति पर उपराज्यपाल के नियंत्रण संबंधी प्रावधान हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी तथा अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।

लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर मानसून सत्र के आखिर में आठ, नौ और 10 अगस्त को चर्चा होगी।

दिल्ली संशोधन विधेयक का विरोध करेगा बीआरएस

नयी दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्ववाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2023' को पारित करने का विरोध करेगी तथा इसके लिए पार्टी ने राज्यसभा समेत अपने सभी सांसदों को व्हीप भी जारी किया है। बीआरएस (राज्यसभा) के सभी संसद सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक के खिलाफ मतदान करें। बीआरएस (राज्यसभा) के सभी संसद सदस्य 31 जुलाई से चार अगस्त तक सदन में तक तक उपस्थित रहेंगे जब तक विधेयक पर मतदान समाप्त नहीं हो जाता। गौरतलब है कि विपक्ष के भारी विरोध के बीच सरकार ने बहुचर्चित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2023' को सदन में चर्चा तथा पारित कराने के लिए मंगलवार को लोकसभा में पेश किया।

गौरवशाली भारत
नई दिल्ली
बुधवार 02 अगस्त 2023
Www.gauravshalibharat.com

संपादकीय

लोगों में संविधान के प्रति भरोसा पैदा करना बहुत जरूरी

मणिपुर का मामला दरअसल, राज्य सरकार की लापरवाही और केंद्र सरकार की शिथिलता का नतीजा है।

मणिपुर मामले में एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। उसने कुछ कड़े सवाल किए हैं, जिनका जवाब देना राज्य प्रशासन के लिए आसान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो खो गया, वह खो गया, मगर अभी सवाल लोगों में विश्वास बहाली का है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसका ब्योरा दे।

मामला केवल दो महिलाओं का नहीं है, ऐसी अनेक महिलाओं का वहां उत्पीड़न हुआ है, उनका क्या विवरण है। उन दो महिलाओं की प्राथमिकी दर्ज करने में चौदह दिन क्यों लग गए, जिन्हें निर्वस्त्र करके घुमाने का वीडियो प्रसारित हुआ और प्रशासन तभी हरकत में क्यों आया, जब वह वीडियो प्रसारित हो गया। सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि छह हजार प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, तब अदालत ने पूछा कि उनमें से कितनी प्राथमिकियां महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों से जुड़ी हैं।

इसका कोई स्पष्ट उत्तर सरकार के पास नहीं था। हालांकि दोनों महिलाओं से जुड़े मामले की जांच सीबीआइ ने अपने हाथ में ले ली है, मगर सर्वोच्च न्यायालय मणिपुर में हुई ऐसी तमाम घटनाओं की जांच के पक्ष में है और वह इसके लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी में जांच कराना चाहता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

मणिपुर का मामला दरअसल, राज्य सरकार की लापरवाही और फिर केंद्र सरकार की शिथिलता का नतीजा है। अगर सरकारों ने इस मामले पर काबू पाने की कोशिश की होती, तो कोई कारण नहीं कि यह इतने लंबे समय तक चलता रहता और वहां करीब दो सौ लोगों की जान चली जाती, हजारों लोगों को बेघर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ता।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मत कहिए कि वहां एक समुदाय के खिलाफ हिंसा हुई, संदेश यह जाना चाहिए कि वहां एक भी समुदाय के खिलाफ हिंसा से कड़ाई से निपटा जाएगा। लोगों में संविधान के प्रति भरोसा पैदा करना बहुत जरूरी है। दरअसल, मणिपुर में पिछले करीब तीन महीने से हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, मगर इस पर पूरी दुनिया में कठोर निंदा का सिलसिला तब शुरू हुआ, जब दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का वीडियो प्रसारित हुआ। इस तरह मणिपुर में चल रही सामुदायिक हिंसा को कई लोगों ने उस वीडियो तक सीमित कर दिया है, जबकि पूरी हिंसा को लेकर ढेर सारे सवाल हैं।

अब अनेक तथ्य प्रकट हैं, जिनसे राज्य सरकार की शह और केंद्र सरकार की उदासीनता उजागर होती है। शस्त्रागार से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस आदि लूट लिया जाना और सरकारों का इस पर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कई सवाल खड़े करता है। विपक्षी दलों ने इन तमाम सवालों को लेकर संसद में जवाब मांगा है, उनके प्रतिनिधि मणिपुर हो आए हैं।

अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल पूछे हैं और उच्चाधिकार प्राप्त समिति से इन घटनाओं से संबंधित जांचों पर निगरानी रखने की बात कही है, उससे राज्य सरकार की लापरवाहियों, पक्षपात और हिंसा को नजरअंदाज करने के तथ्य और स्पष्ट हो सकेंगे। मणिपुर की घटना ने केंद्र सरकार को भी सांसत में डाल दिया है, पूर्वोत्तर के लोगों का भरोसा डिगा है। वहां के दूसरे राज्यों में भी तनाव की आशंका है। ऐसे में वहां तुरंत शांति बहाली के लिए व्यावहारिक कदम उठाने की उम्मीद की जाती है।

बच्चों की तस्करी में यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश सबसे आगे

बच्चों की तस्करी के बाद उसे घरेलू काम में लगाने से लेकर यौन शोषण और देह-व्यापार के भयावह दलदल में भी धकेल दिया जाता है।

रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाने वाले बच्चों का सवाल किसी रपट के जरिए सामने आने के बाद सुर्खियों में आता है, पर कुछ समय बाद फिर सब पहले की तरह शांत हो जाता है। विडंबना यह है कि इस समस्या की गंभीरता के मद्देनजर सरकारों की ओर से हर स्तर पर तंत्र को सक्रिय करने और बच्चों की तस्करी पर काबू पाने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद आने वाली कोई रिपोर्ट यही बताती है कि इस मोर्चे पर पर्याप्त संवेदनशील तरीके से काम नहीं किया गया।

गौरतलब है कि बच्चों की समस्याओं पर काम करने वाली एक संस्था की ओर से रविवार को जारी रिपोर्ट में फिर से बाल तस्करी की चिंताजनक तस्वीर सामने रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 से 2022 के बीच देश भर में बहुत सारे बच्चे गायब हुए, लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में बच्चों की तस्करी के सबसे अधिक मामले सामने आए। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में भी हालत बेहद अफसोसनाक रही, जहां बाल तस्करी के मामलों में अड़सठ फीसद की बढ़ोतरी देखी गई।

सवाल है कि एक तरफ देश भर में राज्य सरकारें हर स्तर पर बेहतर सुशासन, नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा आदि का आश्वासन देती रहती हैं, लेकिन क्या उन पर उतनी ही संवेदनशीलता से अमल करने को लेकर भी वे गंभीर रहती हैं? आखिर बच्चों की तस्करी के अमानवीय कारोबार में लगे लोगों या गिरोहों को किसी बच्चे को गायब करने या खोए हुए बच्चों को उठा कर कहीं बेच देने की हिम्मत कहां से आती है?

अगर अपराध के खिलाफ तंत्र की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हों तो क्या बाल तस्करों को इतने व्यापक पैमाने पर अपनी साजिशों को अंजाम देने का मौका मिल पाएगा? विडंबना है कि शहरों-महानगरों में चल रही कुछ औद्योगिक इकाइयों में कई बार तेरह से अठारह वर्ष के बीच के बच्चों से काम कराया जाता है।

लेकिन सभी कारखानों और उसकी समूची संरचना को जांच के दायरे में मानने वाले सरकारी तंत्र को बाल मजदूरी और तस्करी के पहलू पर गंभीरता से काम करने की जरूरत नहीं लगती है! आखिर वे कौन-सी वजहें हैं कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, न केवल जयपुर शहर को देश में बाल तस्करी के मुख्य केंद्र के रूप में दर्ज किया गया, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कई स्थानों को इसी कोटि में पाया गया। जबकि माना जाता है कि मुख्य शहरों में कानून-व्यवस्था देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी होती होगी!

हालांकि बच्चों के जीवन पर जोखिम के मसले पर काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इसी अवधि में साढ़े तेरह हजार से ज्यादा बच्चों को बचाया भी गया। फिर सरकार की ओर से भी कई सकारात्मक कदम उठाए गए। लेकिन एक पहलू यह भी है कि एक ओर पुलिस-प्रशासन की चौकसी और आधुनिक तकनीकी के उपयोग के जरिए हर स्तर पर आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखने और लगाम लगाने का दावा किया जाता है, दूसरी ओर जघन्य अपराध तक बदस्तूर जारी रहते हैं।

इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है कि जो बच्चे लापता हो जाते हैं, उनके घर में मां-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों की हालत क्या होती होगी! इससे इतर, गायब हो गए बच्चों को किस त्रासदी से गुजरना पड़ता होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। खासतौर पर जो बच्चियां तस्करों के हाथ लग जाती हैं, उन्हें घरेलू काम में लगाने से लेकर यौन शोषण और देह-व्यापार के भयावह दलदल में भी धकेल दिया जाता है।

बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पर विशेष लेख

प्लास्टिक पॉल्यूशन-वैश्विक समस्या और समाधान

डॉ. अशोक कुमार गदिया

संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' घोषित किए जाने के बाद प्लास्टिक प्रदूषण एक बार फिर से चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र की स्टडी के मुताबिक पूरे विश्व में हर साल 400 मिलिटन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से सिर्फ 50 फीसदी का ही फिर से प्रयोग होता है और सिर्फ 10 प्रतिशत की ही रिसाइकिलिंग हो पाती है। ऐसे में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा हमारे पर्यावरण को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे पहाड़ों, तालाबों, नदियों और समुद्र में पहुंच जाता है।

महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति

1-महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन के प्रतीक हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। पृथ्वी पर जीवन का आरम्भ महासागरों से माना जाता है, जिनमें असीम जैव विविधता का भंडार समाया है। पृथ्वी का लगभग सत्तर प्रतिशत भाग महासागरों से घिरा है। पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का लगभग सत्तानवे प्रतिशत जल महासागरों में समाया हुआ है। महासागरों की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर पृथ्वी के सभी महासागरों को एक विशाल महासागर मान लिया जाए तो उसकी तुलना में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक छोटे द्वीप से प्रतीत होंगे।

2-हाल के वर्षों में महासागरों में बढ़ता प्रदूषण चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। अरबों टन प्लास्टिक का कचरा हर साल महासागरों में समा जाता है। आसानी से विघटित नहीं होने के कारण यह कचरा महासागरों में जस का तस पड़ा रहता है। अकेले हिन्द महासागर में भारतीय उपमहाद्वीप से पहुंचने वाली भारी धातुओं और लवणीय प्रदूषण की मात्रा प्रतिवर्ष करोड़ों टन है। विषैले रसायनों के रोजाना मिलने से समुद्री जैव विविधता भी प्रभावित होती है। लेकिन वायु और अन्य प्रकार के प्रदूषण से समुद्र के इस कदर प्रदूषित होते जाने को लेकर उसी अनुपात में चिन्ता नहीं दिखाई देती।

3-गौरतलब है कि प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी की सतह का यह लगभग तीस प्रतिशत हिस्सा है। इस महासागर की गहराई पैंतीस हजार फुट और इसका आकार त्रिभुज की तरह का है। प्रशांत महासागर में करीब पच्चीस हजार द्वीप हैं। अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पास पृथ्वी का इक्कीस प्रतिशत से अधिक भाग है। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के अंक आठ यानी 8 की संख्या के जैसा है। इस महासागर की कुछ वनस्पतियां खुद से चमकती हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बढ़ा महासागर है। यह धरती का लगभग चौदह प्रतिशत हिस्सा है। हिन्द महासागर को रत्नसागर नाम से भी जाना जाता है।

हिन्द महासागर इकलौता ऐसा महासागर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। अंटार्कटिका महासागरों में चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसको आस्ट्रल महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इस महासागर में आइसबर्ग यानी पहाड़ की तरह दिखते बर्फ के विशालकाय टुकड़े तैरते हुए देखे जाते हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन के अन्दर चार सौ से भी अधिक झीलें हैं। आर्कटिक महासागर पांच महासागरों में सबसे छोटा और उथला महासागर है। इसे उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। सर्दियों में यह महासागर पूर्णत: समुद्री बर्फ से ढ़का रहता है।

4-हम सांस लेने के लिए जिस आक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उसकी दस फीसद मात्रा हमें समुद्र से ही प्राप्त होती है।

समुद्र में मौजूद सूक्ष्म बैक्टीरिया या जीवाणु आक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए बेहद जरूरी है। समुद्र में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की वजह से ये बैक्टीरिया पनप नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण समुद्र में आक्सीजन की मात्रा भी घट रही है। पहले ही जलवायु परिवर्तन या अन्य वजहों से समुद्रों की प्रकृति में अक्सर तेज बदलाव होता देखा जा रहा है, जो कभी व्यापक विनाश का कारण बन सकता है। अगर हम समय रहते नहीं चेते तो यह पशु-पक्षियों के साथ-साथ इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।

समुद्र में कचरा फैलाने वाले देश
चीन 88 लाख मीट्रिक टन
इंडोनेशिया 32 लाख मीट्रिक टन
फिलीपींस 19 लाख मीट्रिक टन
वियतनाम 18 लाख मीट्रिक टन
श्रीलंका 16 लाख मीट्रिक टन
मिश्र 10 लाख मीट्रिक टन
थाईलैंड 10 लाख मीट्रिक टन
मलेशिया 09 लाख मीट्रिक टन
नाइजीरिया 09 लाख मीट्रिक टन
बांगलादेश 08 लाख मीट्रिक टन
अमेरिका 03 लाख मीट्रिक टन

इसी तरह हजारों टन कचरा पहाड़ों पर हर वर्ष पर्यटक लोग फेंककर आ जाते हैं। उसमें भी मुख्य रूप से प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का कूड़ा ही होता है। विश्व की बड़ी से बड़ी पहाड़ी चोटियों पर हजारों टन कूड़ा बिखरा पड़ा है जो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने, असमय अत्यधिक वर्षा एवं असमय सूखे का कारण बन रही है।

यह कूड़ा फेंकने का दुष्कर्म अगर समय रहते बन्द नहीं हुआ तो मानव वनस्पति एवं जीव-जन्तु का विनाश अवश्यमभावी है। अभी हाल ही की जानकारी में पता लगा की अकेले माउन्ट एवरेस्ट पर 35,000 किलो कूड़ा हटाने की योजना नेपाल सरकार ने बनाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि माउन्ट एवरेस्ट जैसी सबसे ऊँची चोटी पर इससे कई गुना कुड़ा जमा हुआ है।

नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति-

इसी प्रकार भारत की लगभग सभी नदियों में हमारी जनता एवं सरकारें बेरोक-टोक सहजता से स्वाभाविक रूप से लाखों टन कूड़ा प्रवाहित करती हैं और फिर नदियों को साफ करने की बातें करती हैं। कैसी विडम्बना है एक तरफ हम अपनी नदियों को जीवनदायिनी पवित्र एवं माता का दर्जा देते हैं दूसरी ओर उसी में सारी गंदगी प्रवाहित करते हुए इसे पूण्य मानते हैं।

शहरों-गांवों में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति-

भारत के किसी भी शहर या गाँव में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर, रेल की पटरियों के किनारे, रोड के दोनों तरफ एवं खेत-खलिहानों के किनारों पर प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के कूड़े का ढ़ेर आपका स्वागत करता मिलेगा। इससे हमारे स्वच्छ भारत की सारी कल्पनाएं धूमिल होती नजर आती हैं। ऐसी अनचाही गन्दगी का विकराल एवं वीभत्स रूप हमें हर जगह दिखाई देता है। जिसका हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते।

यह है समाधान-

इस समस्या का एक ही समाधान है कि हम एक बार प्रयोग आने वाली पॉलिथीन या प्लास्टिक उत्पादन ही बन्द कर दें एवं जो अभी तक बना हुआ है उसे कृत्रिम कुंआ बनाकर उसमें दफना दें। ताकि आने वाले पचास-सौ वर्षों में वह नष्ट हो जाए। इस तरह के कुंए हमें हर गाँव-शहर में बनाने होंगे। यह सब हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, जोकि मानवजनित दुशवारियां हैं। इसे हमें ही रोकना होगा।

(लेखक मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के कुलाधिपति हैं।)

शिक्षा बीच में छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति चिन्ताजनक

आजादी के अमृतकाल को सार्थक करने में शिक्षा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। कहा जा सकता है कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार भी है जिससे इंसान न केवल खुद को, बल्कि समाज, राष्ट्र एवं दुनिया को भी बदल सकता है। बात जब नया भारत-सशक्त भारत बनाने की हो रही है तो शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने एवं सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन चिंता की बात यह है कि सरकारों की इस सकारात्मक सोच के बावजूद हमारी शिक्षा प्रणाली विपरीत संकेत देती रही है। भारत में उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा में छात्र-छात्रों के ड्रॉपआउट्स की संख्या यानी बीच में ही पढ़ाई छोड देने की संख्या बढ़ना न केवल शिक्षा-व्यवस्था पर बल्कि सरकार की शिक्षा नीति एवं व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। संसद में दिये गये एक जबाव के अनुसार देश के नामी उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले पांच साल के दौरान 34 हजार से ज्यादा छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ गए। दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सन् 2022 की बोर्ड परीक्षाओं के विश्लेषण में बताया गया है कि दसवीं और बारहवीं के स्तर पर देश में लाखों बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। विश्लेषण के मुताबिक, पिछले साल पैंतीस लाख विद्यार्थी दसवीं के बाद ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने नहीं गए। इनमें से साढ़े सत्ताइस लाख सफल नहीं हुए और साढ़े सात लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। इसी तरह, पिछले साल बारहवीं के बाद 2.34 लाख विद्यार्थियों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। इनमें से सतहत्तर फीसद ग्यारह राज्यों से थे। यानी करीब अट्ठावन लाख विद्यार्थी दसवीं और बारहवीं में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो यह किसी भी सरकार के लिए बेहद चिंता की बात होनी चाहिए और यह समग्र शिक्षा व्यवस्था से लेकर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर अमल पर सवालिया निशान है।

बात उच्च शिक्षा की करें तो वैश्विक मापदण्डों पर हमारी शिक्षण संस्थाएं काफी पीछे नजर आती हैं। यह तो तब है जब आजादी के 76 सालों में सरकारों ने शिक्षा के प्रसार की दिशा में काफी प्रयास किये, बहुआयामी योजनाओं को आकार दिया एवं बजट में भी भारी भरकम प्रावधान किये हैं। 34 हजार से ज्यादा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों में भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी ज्यादा हैं। ये संस्थान कोई सामान्य सरकारी कॉलेज नहीं बल्कि आइआइटी, एनआइटी और आइआइएसईआर, आइआइएम व केन्द्रीय विश्वविद्यालय और इनके जैसे स्तर के हैं। ऐसे संस्थानों में क्या पढ़ाई का स्तर व माहौल उचित नहीं है? सरकार और देश के शिक्षाविदों को इस तथ्य को लेकर भी चिंता करनी ही होगी कि बीते पांच साल में इन उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले 92 विद्यार्थियों ने पढ़ाई के बीच में ही आत्महत्या क्यों कर ली? ऐसे ही आईआईटी बुम्बई के फर्स्ट ईयर के छात्र दर्शन सोलंकी ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली, इसके बाद वहां के छात्रों से अधिकारिक तौर पर कहा गया है कि छात्र एक दूसरे से जी (एडवांस) रैंक या गेट स्कोर के बारे में पूछताछ न करें। न ही ऐसा कोई सवाल करें जिससे छात्र की जाति और उससे जुड़े पहलू उजागर होते हो।

फ़क़ीरों को भला किसका डर होगा

फ़क़ीरों को भला किसका डर होगा,
है खुदा, तो भला किसका डर होगा।

खुशियाँ बांटिए, तेजी से हैं बढती,
गमों का भला हम पर क्या असर होगा।

उसके लिए है हर पल आनंद ही आनंद
फसानों का भला उस पर क्या कहर होगा।

दो पल की माया है दौलत, शोहरत,
फकीरों के लिए यह बड़ा जहर होगा।

खुशी और गम,सिक्के के दो पहलु,
सोचो गम न हो तो कैसा शहर होगा।

जिंदगी की जंग जीतेगा वहीँ,
जो ईमान का सच्चा हमसफ़र होगा।

आज जी ले,जोश जूनून के संग,
अगला पल,बेइंतहा बेहतर होगा।

कर उपवास ईश्वर के नाम संजीव,
ऊपर वाला ही तेरा रहबर होगा।

संजीव ठाकुर
रायपुर

मानसून सत्र 2023 का हाल देखकर आगे मतदान का प्रयोग सोच समझकर कीजिएगा जी!

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत दुनियां का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में विख्यात है,जिसकी अनेक देशों में मिसालें दी जाती है कि हर विषय व बिल पर खुलकर चर्चा कर आम सहमति बनाते हुए विषयों का व कानूनों की गुणवत्ता को निखारा जा सके, जिसका सटीक उदाहरण हमारा आज का संविधान है, जिसकी संविधान सभा की बहस दिसंबर 1946 से जनवरी 1950 तक चली थी उस कवायद का मकसद था आदेश रूप में संसदीय बहस की परंपरा बहाल रखते हुए उसे मजबूती दी जाए।सांसदों के लिएविवेकसम्मत तरीके से मतदान की इजाजत हो ताकि विमर्श की अपेक्षित प्रक्रिया पुनर्जीवित हो।ब्रिटिश में पीएमको हर बुधवार को हाउस आफ कॉमनस में सांसदों के प्रश्नों का जवाब देना होता है विपत्ति अवधि कोविड-19 के दौरान भी पीएम ने वर्चुअली सांसदों के सवालों का जवाब देना देना पड़ा था जबकि भारत में उस अवधि में प्रश्नकाल की भी समाप्त कर दिया गया था। मेरा मानना है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनी रचनात्मक दरकरार के साथ पक्ष-विपक्ष की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए और सांसदों को स्वायत्त पहलू की भी इजाजत हो। भारत में अनुमानत: एक संसद सदस्य 25 लाख से अधिक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भूटान वहबोत्सवाना स्लोवेनिया जैसे अनेक छोटे देशों की आबादी से भी बड़ा है जो अनुमानत: 2026 तक नए सीमांकन और अनुपात गणित के हिसाब से लोकसभा की एक हजार से अधिक सीटें हो सकती है। जाहिर है भारत के लिए विशाल समय संसाधन लगेंगे इसलिए ही नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। परंतु जिस तरह से मानसून सत्र-2023 का हाल आज भारत सहित पूरी दुनियां देख रही है कि 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र में आज 1 अगस्त 2023 भी निकल गया है परंतु संसद के दोनों सदन बाधित हैं। 8 दिनों में केवल 18 घंटे ही काम हुआ है आज पारित चलचित्र अधिनियम 2023 बिल सहित सभी बिल दोनों सदनों में ध्वनिमत से ही पारित हो रहे हैं न कि किसी भी प्रकार की चर्चा थी, क्योंकि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर संसद में पीएम के बयान की मांग पर अड़ा है तो पक्ष का बयान है कि विपक्ष चर्चा के लिए भाग रहा है। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों को कुछ झुककर रास्ता निकालना चाहिए। पीएम को संसद में बयान देने की मांग को संभवत स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इसके पूर्व दशक में भी इसी सत्ताधारी पक्ष की मांग पर वर्तमान विपक्ष के तत्कालीन पीएम को आखिर झुककर बयान देना पढ़ा था जिसकी चर्चा हम नीचे पैरा में करेंगे, या फिर विपक्ष ने चूंकि अविश्वास बिल का प्रस्ताव लाया है जो स्वीकार कर लिया गया है, तो स्वाभाविक ही है पीएम के बयान की संभावना है इसलिए सदन चलने में सहयोग देने पर विचार करना चाहिए। चूंकि दोनों पक्षों के उड़ने से बाधित संसद की कार्यवाही में संभवत: हर मिनट में ढाई लाख रुपए खर्च होते हैं याने 1 घंटे में ढाई करोड़ रुपए खर्च होते होंगे जो टैक्सपेयर्स की गाड़ी कमाई है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, मानसून सत्र 2023 बाधित-लोकतंत्र को धरातल पर उतारने पक्ष विपक्ष दोनों की ज़वाबदेही ज़रूरी-झुकना सर्वश्रेष्ठ माननीय गुण है।

साथियों बात अगर हम मानसून सत्र 2023 की करें तो संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 12 दिन हो चुके हैं, इस बीच संसद के दोनों सदनों में 8 दिन की बैठकें हुई हैं, हालांकि बैठकों के हिसाब से तो 8 दिन हो गया है, लेकिन अगर सदन की कार्यवाही की बात करें तो ये लगातार बाधित होते रही है। पिछले कुछ सालों से ऐसा लगने लगा है कि संसद की लगातार बाधित होती कार्यवाही संसदीय प्रक्रिया का मूलभूत हिस्सा बन चुका है। हालांकि सैद्धांतिक तौर से ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवहार में हम ऐसा ही देख रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान भी मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी का खामियाजा संसद की कार्यवाही को भुगतना पड़ रहा है। सोमवार यानें 31 जुलाई को भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में हंगामा और अवरोध का ही बोलबाला रहा। इसी माहौल में लोकसभा से चलचित्र विधायक 2023 को भी पारित करवा लिया गया। संसद के मानसून सत्र में हुए हंगामे और सत्ता पक्ष और विपक्ष में बढ़ते टकराव से देश बहुत चिंतित है। देश में विकास की बयार बहे इसके लिए जरूरी है कि परस्पर संवाद कावातावरण बना रहे। यह हो सकता है अगर सांसद अपने संकल्प को याद करें। संसद के पचास साल पूरे होने पर पीए संगमा की अध्यक्षता में हर दल और समूह की सहमति से निर्णय किया गया था कि प्रश्नकाल में व्यवधान पैदा नहीं किया जाएगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं कम से कम इसमें एक संकल्प सांसद करें तो संसदीय लोकतंत्र में सुधार की शुरुआत हो सकती है, लेकिन क्या हमारे आजकल के सांसद यह संकल्प लेने की स्थिति में हैं? यह खतरा सिर्फ सांसदों के संकल्प करने से नहीं हटेगा क्योंकि आजकल के सांसद यह संकल्प लेने में समर्थ हैं? संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है, माना ये भी जाता है कि विपक्ष संसद में कार्यवाही को बाधित करते हुए कहीं न कहीं किसी रणनीति पर काम कर रहा है। बताते चलें कि केंद्र की तरफ से दिल्ली अध्यादेश समेत बहुत से विधेयक इस मॉनसून सत्र में लाए जाने हैं।

साथियों बात अगर हम मणिपुर मुद्दे पर संसद में पीएम के बयान की मांग बनाम विपक्ष चर्चा से भाग रहा है बयान की करें तो, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन भारी हंगामे के कारण यह स्थगित हो जा रहा है, आज भी बिना किसी सार्थक चर्चा के लोकसभा के सत्र को स्थगित कर दिया गया। दरअसल विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहता है, सत्ताधारी पार्टी भी कह रही है कि हम इस विषय पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन फिर भी संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता है और स्थगित कर दिया जाता है। विपक्षी नेता पीएम की चुप्पी पर भी निशाना साध रहे हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के दौरान पीएम ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि यह घटना शर्मसार करने वाली है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा दरअसल विपक्षी दल मणिपुर मुद्दे पर सदन में पीएम के बयान की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण संसद के मानसून सत्र में व्यवधान देखने को मिल रहा है।ऐसे में यह याद करना भी जरूरी है कि यूपीए सरकार के दौरान सदन की स्थिति क्या रहती थी। बता दें कि यूपीए सरकार के दौरान ऐसे कई मौके आए जब विपक्ष यानी वर्तमान सत्ता पक्ष की मांग पर पीएम माननीय सिंह ने संसद में बयान दिया था। साथियों बात अगर हम करीब एक दशक पूर्व भी ऐसी ही स्थिति पर वर्तमान सत्ताधारी तब विपक्ष द्वारा पीएम के बयान की मांग की करें तो, 4 मार्च, 2011 कोकेंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पी.जे. थॉमस की नियुक्ति का मुद्दा संसद में गूंजा था तब विपक्ष ने मांग की कि पीएम पूरे प्रकरण पर बयान दें। विपक्ष की मांग को मानते हुए तत्कालीन पीएम को संसद में आकर बयान देना पड़ा था।दरअसल 7 मार्च, 2011 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पी.जे.थॉमस की नियुक्ति को गलती बताते हुए पीएम ने कहा था कि वह इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। सरकार नए सीवीसी की नियुक्ति करते समय कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों/निर्देशों को ध्यान में रखेगी। 20 अगस्त, 2013 को सरकार पर कोयला घोटाले को छुपाने का आरोप लगाते हुए, वर्तमान सत्ता पक्ष तब विपक्ष ने कोयला ब्लॉक आवंटन पर गायब फाइलों पर पीएम सिंह से बयान की मांग करते हुए संसद को बाधित कर दिया था, इसके 10 दिन बाद याने 30 अगस्त, 2013 को कोयला खदानों के आवंटन से संबंधित गुम फाइलों को लेकर हमले के बीच, पीएम ने कहा था कि वह कोयला मंत्रालय की फाइलों के संरक्षक नहीं हैं, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी दोषी व्यक्ति को सरकार द्वारा बचाया नहीं जाएगा।

शार्ट न्यूज

रील बनाते वक्त ट्रेन की चपेट में आकर मौत

मुरादाबाद। मुरादाबाद में दोस्तों संग रेल ट्रैक पर रील बना रहे एक ऑटो चालक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को उसके दोस्तों ने ट्रेन के आगे धक्का दिया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन में जुटी है। घटना मझोला थाना क्षेत्र में भोला सिंह की मिलक के पास की है। रविवार शाम यहां ट्रेन की चपेट में आकर टैंपो चालक (22साल) जीशान की मौत हो गई थी। उसके पिता ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए थे और मारपीट करने के बाद उन्होंने उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया। पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। पाकबड़ा के जुम्मेरात का बाजार निवासी राशिद का बेटा जीशान टैंपो चलाता था। पिता का कहना है कि रविवार दोपहर करीब 3 बजे उनके बेटे जीशान को पाकबड़ा निवासी उसके दो दोस्त मेला दिखाने की बात कहकर घर से बुलाकर ले गए थे। आरोप है कि ये दोनों दोस्त जीशान को मझोला थाना क्षेत्र के भोला सिंह की मिलक के पास स्थित रेलवे ट्रैक के किनारे ले गए। यहां दोनों दोस्तों ने उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान मुरादाबाद की ओर से ट्रेन आई तो जीशान को ट्रेन के आगे फेंक दिया। ट्रेन की चपेट में आने से जीशान गंभीर रूप से घायल हो गया।

इटावा में पुलिस मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल

इटावा। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के बसरेहर इलाके में मंगलवार तड़के पुलिस ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद दो लुटेरों को घायलावस्था में धर दबोचा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लुटेरों ने सोमवार सुबह सिविल लाइन के शिवा कालोनी में पूजा करके लौट रही एक महिला से सोने की चेन लूटी थी। बदमाशो के पास से लूटी गई सोने की चेन बरामद कर ली गई है। उन्होने बताया कि एक सूचना के आधार पर पुलिस ने सेंगर नदी के पास अपराधियों की घेराबंदी कर उनको आत्मसमर्पण के लिये कहा मगर बदमाशों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आत्म रक्षार्थ पुलिस की ओर से चलाई गई गोलियों से दो बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि उनका तीसरा साथी मौका है। उन्होने बताया कि सोमवार की सुबह थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शिवा कालोनी में अपने घर के अंदर पूजा करके वापस जा रही थी कि तभी दो बाइक सवार लुटेरों ने महिला के गले से चेन लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी।

रील बनाते वक्त ट्रेन की चपेट में आकर मौत

मुरादाबाद। मुरादाबाद में दोस्तों संग रेल ट्रैक पर रील बना रहे एक ऑटो चालक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को उसके दोस्तों ने ट्रेन के आगे धक्का दिया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन में जुटी है। घटना मझोला थाना क्षेत्र में भोला सिंह की मिलक के पास की है। रविवार शाम यहां ट्रेन की चपेट में आकर टैंपो चालक (22साल) जीशान की मौत हो गई थी। उसके पिता ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए थे और मारपीट करने के बाद उन्होंने उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया। पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है। पाकबड़ा के जुम्मेरात का बाजार निवासी राशिद का बेटा जीशान टैंपो चलाता था। पिता का कहना है कि रविवार दोपहर करीब 3 बजे उनके बेटे जीशान को पाकबड़ा निवासी उसके दो दोस्त मेला दिखाने की बात कहकर घर से बुलाकर ले गए थे। आरोप है कि ये दोनों दोस्त जीशान को मझोला थाना क्षेत्र के भोला सिंह की मिलक के पास स्थित रेलवे ट्रैक के किनारे ले गए। यहां दोनों दोस्तों ने उसके साथ मारपीट की।

पीलीभीत में दिनदहाड़े 13 लाख की चोरी

पीलीभीत। पीलीभीत में पुलिस को चुनौती देते हुए चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए 13 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद परिवार के होश उड़ गए। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल करते हुए पड़ोसियों से भी पूछताछ की। इस घटना के बाद से मोहल्ले में सनसनी का माहौल है। पूरा मामला न्यूरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मझोला का बताया जा रहा है। यहां कस्बे के रहने वाले प्रमुख खाद व्यापारी विजेंद्र भाटिया के परिवार के लोग मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे गुरुद्वारे गए हुए थे। इस दौरान मौका पाकर चोर घर में घुस आए और जेवरात समेत नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया। परिवार के लोग जब गुरुद्वारे से वापस आए तो घर का सामान बिखरा देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आनन-फानन में पूरे मामले की सूचना न्यूरिया थाना पुलिस को दी गई। चोरी की सूचना मिलते ही न्यूरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दिनदहाड़े लाखों की चोरी की वारदात संज्ञान में आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया।

बांदा में तालाब में डूबकर बुजुर्ग की मौत

बांदा। बांदा में 1 दिन पहले बुजुर्ग कमल तोड़ने के लिए तालाब में गया हुआ था, लेकिन गहरे पानी में जाने कारण वह डूब गया और उसका शव पुलिस ने 30 घंटे बाद बरामद किया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत थरथुआ गांव के रहने वाले शंकर पटेल (70) कल सुबह 5 बजे फूल तोड़ने के लिए तालाब गए हुए थे। जब वहां से काफी देर तक घर नहीं आए तो परिजनों ने जाकर देखा तो तालाब के किनारे उनके जूते पड़े हुए थे, लेकिन वृद्ध का कुछ आता पता नहीं था फिर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तालाब में बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन तालाब गहरा और बड़ा होने के कारण शव नहीं मिल सका। आज सुबह वृद्ध का शव पानी में उतारता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं, बबेरू सीओ ने बताया कि एक बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई है और बताया जा रहा है की वह तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे।

फर्रुखाबाद में चाचा ने की भतीजे की हत्या

फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में जमीन के विवाद में चाचा ने लाइसेंसी राइफल से भतीजे की सोमवार की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कई माह से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष पुलिस को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके थे, लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया था। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव धनसुआ में सेवानिवृत्त फौजी भीमसेन राजपूत का अपने भतीजे रामगोपाल राजपूत से जमीन का विवाद चल रहा था। सोमवार की शाम राजकुमार घर पहुंचा। इस दौरान भीमसेन राजपूत जमीन को लेकर गाली-गलौज करने लगे। रामगोपाल ने विरोध किया तो चाचा भीमसेन ने लाइसेंसी राइफल से फायर कर दिया। गोली रामगोपाल के माथे पर लगी और वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया। घटना के बाद मौके से चाचा भाग गया। घायल अवस्था में परिजन रामगोपाल को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी सचिन कुमार सिंह, सीओ प्रदीप कुमार सिंह, एएसपी डॉ. संजय कुमार लोहिया अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली।

जौनपुर में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

जौनपुर। जौनपुर में मोहर्रम पर निकाले गए 10वीं ताजिए में शामिल युवाओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लोगों ने ये नारे पुलिस की मौजूदगी में और रास्ते में शिव मंदिर के पास लगाए। इसका वीडियो बनाकर इस घटना के दो दिन बाद कुछ लोगों ने वायरल कर दिया। स्थानीय लोगों ने नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 33 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सभी को गिरफ्तार कर उनका चालान किया गया है। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के गोधना बाजार का शनिवार देर रात का है। सोमवार रात इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस गोधना बाजार के आसपास के गांव पहुंची। पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ करने के लिए उठाया है। सोमवार रात ही गोधना बाजार समेत आसपास के इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

जनता की समस्या के समाधान में हीलाहवाली पर होगी सख्त कार्रवाई : सीएम

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिखे तल्ख तेवर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्या के समाधान में हीलाहवाली करने वाले अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अगर वह नहीं सुधरे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समय से अपने ऑफिस पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनने के निर्देश दिये और प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण करने को कहा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह तल्ख तेवर मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन के दौरान देखने को मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सौ से अधिक लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, डीजीपी विजय कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे।

सरकार के पास इलाज के लिए पैसे की कोई कमी नहीं

जनता दर्शन में ज्यादातर मामले अवैध कब्जे, आपसी संपत्ति विवाद, आपसी विवाद, इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार को लेकर आए। सीएम योगी ने आए सभी लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार के पास इलाज के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव में किसी भी प्रदेशवासी एवं जरूरतमंद का इलाज नहीं रुकेगा।

उनके प्रार्थना पत्रों पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज से जुड़े एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन को उपलब्ध कराया जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता वह निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए। जनता दर्शन में कुछ लोगों की रोजगार संबंधी समस्या पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक भरोसा देते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

समय पर आफिस पहुंचें अधिकारी, जनता की समस्याओं का करें निस्तारण

जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को निर्देशित किया कि सभी विभागों में जनता से मिलने के समय का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान अधिकारी अपने ऑफिस में मौजूद रहें। यदि वह किसी आवश्यक कार्य के चलते ऑफिस में नहीं उपस्थित हैं तो अपने अधीनस्थ को यह जिम्मेदारी सौंपें ताकि प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की जनता की समस्या का समाधान हो सके। इस मौके पर उपस्थित डीजीपी विजय कुमार को आदेश दिया कि पुलिस प्रशासन से जुड़े मामलों को लटकाया न जाए, उसे समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाए। वहीं इन मामलों को ज्यादा से ज्यादा थाने स्तर पर ही निपटाया जाए ताकि जनता में पुलिस का इकबाल और मजबूत हो सके।

जल पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स बनेंगे यूपी की पहचान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति (यूपी वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी। यह नीति उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू-आधारित, वायु आधारित एवं जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों एवं भूमि खंडों पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश में विंध्य व बुंदेलखंड क्षेत्रों में पहाड़ियां, हिमालय के तराई क्षेत्र में लगभग 16,620 वर्ग किमी. के वन क्षेत्र के साथ अनेक सुंदर परिदृश्य, वन विस्तार, बहती नदियों और लुभावने सुंदर झरने, बांध, जलाशय एवं झीलें होने के चलते प्रदेश में जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा एवं जल क्रीड़ा की काफी संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश में हम इसकी नीति को लेकर आए हैं, जिसे मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल गई है। यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों के लिए वैध होगी।

इस नीति के अंतर्गत कार्यवाही के लिए नोडल एजेंसी मंडल स्तर पर एडवेंचर स्पोर्ट यूनिट का सृजन करेगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट में पूर्व सैनिकों को सम्मिलित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करेगा। नोडल एजेंसी द्वारा अधिसूचित भूखंड क्षेत्रों एवं जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा के लिए क्षमता का अध्ययन कराया जाएगा तथा प्रत्येक भूखंड क्षेत्रों एवं जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। नीति के जारी होने के 60 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी एक विस्तृत एसओपी तैयार करेगी। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में योगी कैबिनेट ने कुछ और बड़े कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत पर्यटन विभाग के बंद पड़े, घाटे में चल रहे या फिर असंचालित पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर विकसित व संचालित किए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बलिया में दामाद की गोली से ससुर की मौत

बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के उभांव क्षेत्र में एक शिक्षक ने अपने चचेरे ससुर की गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बिल्थरा रोड कस्बे में वार्ड नंबर 10 में सोमवार रात करीब 11 बजे सरकारी सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षक ने मनीष सिंह (40) ने कहासुनी के दौरान अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया। इस घटना में उसके चचेरे ससुर शत्रुघ्न सिंह (51) घायल हो गए वहीं अपनी ही गोली से मनीष सिंह खुद भी घायल हो गए। घटना के बाद दोनो घायलों को शामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र बिल्थरा रोड पहुंचाया गया जहां चिकित्सक ने शत्रुघ्न को बेतहर ईलाज के लिए रेफर कर दिया। मऊ ले जाते समय शत्रुध्न की मौत हो गई। मामले में कार्यवाही करते हुए मंगलवार को पुलिस ने मनीष सिंह को हिरासत में ले लिया है तथा उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी राजीव मिश्र ने बताया कि मनीष सिंह की तबियत खराब रहती है तथा उसका इलाज लखनऊ में चलता है। मनीष की तबियत खराब देख उसकी पत्नी नेहा ने अपने चाचा शत्रुघ्न सिंह को बुला लिया। सोमवार की रात्रि सभी लोग भोजन कर एक कमरे में ही सो गए। रात्रि 11 बजे मनीष अचानक जग गया और स्वप्न में हत्या होने की बात कहते हुए अपना पिस्टल ढूढने लगा। नेहा ने मनीष की तबियत खराब देखकर उसका पिस्टल दूसरे कमरे में रख दिया था। इसको लेकर मनीष नेहा पर गुस्सा हो गया। इसके बाद नेहा ने पिस्टल लाकर मनीष को दे दिया।

मिर्जापुर में पत्नी की हत्या कर की आत्महत्या

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के कछवा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी और बाद में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। अपर पुलिस अधीक्षक श्री कांत प्रजापति ने बताया कि क्षेत्र के बजरडीहा गांव निवासी देवनाथ पटेल का पुत्र राजेश पटेल (40) ने आज सुबह अपनी पत्नी नीतू (36) की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। उसके बाद राजेश ने खुद जहरीले प्रदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन उसे इलाज के लिए कछवा अस्पताल ले गए। डाक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे वाराणसी रेफर कर दिया।

विवादित बयानबाजी सपा और भाजपा की राजनीतिक साजिश का हिस्सा : मायावती

एजेंसी

लखनऊ। ज्ञानवापी मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कटाक्ष करते हुये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं द्वारा विवादित बयानबाजी दोनो दलों की राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकती है।

मायावती ने ट्वीट किया सपा द्वारा बौद्ध मठ को तोड़कर बद्रीनाथ मन्दिर बनाने सम्बंधी बयान के बाद अब भाजपा द्वारा कोर्ट में लम्बित ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर विवाद को बढ़ाने वाला बयान कहीं इन दोनों पार्टियों की सोची-समझी राजनीतिक साजिश का परिणाम तो नहीं। यह गंभीर व अति-चिन्तनीय।

उन्होने कहा जबकि ज्ञानवापी मामले में एएसआई से सर्वे कराने के विवाद को लेकर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में अभी लम्बित है, तब उस विवाद के सम्बंध में कोई भी टीका-टिप्पणी करना अनावश्यक ही नहीं बल्कि अनुचित। कोर्ट के फैसले का सम्मान एवं इंतजार करना जरूरी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साक्षात्कार में कहा था कि ज्ञानवापी परिसर में त्रिशूल और देव आकृतियां वहां मंदिर होने की गवाही देती हैं। इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदरीनाथ धाम को बौद्ध मठ करार कर वहां एएसआई सर्वे की वकालत की थी।

मैनपुरी में सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत

अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंदा, मौके से हुआ फरार

मैनपुरी। मैनपुरी में एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक पर सवार तीन युवकों को रौंद दिया। तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक थोड़ा आगे जाने के बाद पलट गया। वहीं ट्रक चालक व परिचालक हादसे की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है।

घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। मरने वाले युवकों के नाम मोहम्मद कैफ, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद सैफ है। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

ये सड़क हादसा बरनाहल थाना क्षेत्र के इकहरा प्राथमिक विद्यालय के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार थाना बरनाहल क्षेत्र के गांव दिहुली निवासी मोहम्मद हसन के घर उनके रिश्तेदार आए हुए थे। सभी बुलेट पर सवार होकर किसी काम से बरनाहल गए थे। बाइक पर मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद हसन (उम्र 18 साल) निवासी ग्राम देहुली थाना बरनाहल मैनपुरी, मोहम्मद आमिर पुत्र शकील खान (उम्र 20 वर्ष) निवासी जाटवपुरी थाना रसूलपुर फिरोजाबाद और मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद असलम निवासी मोहम्मद गंज थाना रसूलपुर फिरोजाबाद बैठा था। तीनों बुलेट से कहीं जा रहे थे तभी पीछे से उनको ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे बाइक पर सवार तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि एक्सीडेंट करने के बाद बेकाबू हुआ ट्रक आगे जाकर नाले में पलट गया। ट्रक में मक्का के बोरे भरे हुए थे। जो सड़क पर फैल गए।

मेरठ में पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़

मेरठ। मेरठ की मवाना पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को पैर में गोली लग गई। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों के पास से एक क्विंटल 20 किलो गोमांस, दो तमंचे, दो कारतूस, दो खोखा कारतूस और कटान करने वाले हथियार बरामद किए। पुलिस ने घायल बदमाशों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया। एसपी देहात कमलेश बहादुर सिंह ने बताया कि मवाना थाना क्षेत्र के ग्राम सठला के जंगल में गोकशी चल रही थी। तभी प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह और उनकी टीम ने जंगल में दबिश दी। पुलिस से खुद को घिरते देख तस्करों ने फायरिंग कर दी।

5 साल पुराने मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला

जालौन में सगे भाइयों को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना

जालौन। जालौन में लगभग 5 साल पहले गोहन थाना क्षेत्र में दिवाली की पूजा करने के लिये खेत पर जा रहे एक युवक की दो सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी से हमला करके बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सगे भाइयों को दोषी मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। दोनों को हिरासत में लेकर जिला कारागार उरई भेज दिया गया है। इस मामले की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि यह मामला लगभग 5 साल पुराना है। जहां गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम भाऊपुरा के रहने वाले धीरेंद्र उर्फ अन्नू अपने बड़े भाई रविंद्र उर्फ चिंटू के साथ 7 नवंबर 2018 को दीपावली की पूजा करने के बाद खेत पर पूजा अर्चना करने के लिये जा रहे थे।

जब वह गांव के बाहर पहुंचे ही थे, तभी रास्ते में गांव के ही रहने वाले दो सगे भाई गजेंद्र और नीरज पुत्रगण जयराम ने रविंद्र उर्फ चिंटू के ऊपर अचानक कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला कर दिया।

मऊ में अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री पर चला बुल्डोजर

मऊ। मऊ जनपद में अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरबीओ एक्ट के तहत नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। दो मंजिला आलीशान मकान में अवैध असलहा बनाया जाता था। पहले इसे कुर्क किया गया और फिर जमींदोज कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान नगर मजिस्ट्रेट के साथ क्षेत्राधिकारी नगर व उप जिलाधिकारी सदर उपस्थित रहे। यह पूरा मामला नगर क्षेत्र के थाना दक्षिण टोला अंतर्गत प्यारेपुरा का है। जहां आरबीओ एक्ट के तहत दो मंजिला आलीशान मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। पहले इस मकान में बिहार के रहने वाले कुछ लोगों द्वारा अवैध असलहा बनाकर सप्लाई किया जाता था। प्रशासन को जब जानकारी मिली तो भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में अर्ध निर्मित असलहा बरामद किए गए। कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और कुछ दिनों बाद उक्त मकान को कुर्क कर दिया गया।

फिरोजाबाद में कार और ऑटो में टक्कर, 3 की मौत

शिकोहाबाद में हुआ एक्सीडेंट, ऑटो चालक की मौके पर ही मौत

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में मंगलवार को भीषड़ सड़क हादसा हो गया। कार और आटो की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इस हादसे के दौरान चीख पुकार मच गई।

हादसा मंगलवार दोपहर करीब दो बजे हुआ। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एटा चौराहा पर एक कार और आटो की भीषण भिड़ंत हो गई। ऑटो चालक अजय मंगलवार दोपहर को करीब पांच सवारियां भरकर शिकोहाबाद से जसराना आ रहा था। जब ऑटो मां अंजनी स्कूल के समीप पहुंचा, तभी जसराना से आ रही वैगन-आर कार संख्या यूपी 83 ए-7930 की आमने-सामने की टक्कर हो गई।

हादसा इतना भीषण था कि ऑटो में सवार यात्री इधर-उधर छिटक गईं, वहीं एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चालक समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। हादसा होते ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को संयुक्त चिकित्सालय भेजा।

यहां इमरजेंसी में तैनात स्टाफ ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में तैनात डॉक्टर ने परीक्षण के बाद तीन को मृत घोषित कर दिया। ऑटो चालक अजय कुमार (16) पुत्र धर्मेंद्र निवासी यदुवंश नगर प्रतापपुर चौराहा और एक महिला 35 जिसका नाम रिंकी (35) पत्नी रवी निवासी जसराना बताया जा रहा है, जबकि एक मृतक युवक (25) की शिनाख्त नहीं हो सकी।

हादसे में ऑटो चालक की मौत की जानकारी होते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजन करुण क्रंदन करते हुए जिला अस्पताल पहुंच गये। वहीं हादसे में घायल कीमत (16), किश्मत (18) पुत्र लटूरी सिंह और मुन्नी चौहान (25) पुत्री पूरनचंद्र निवासी घाघऊ जसराना का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।

बिजली कटौती से परेशान किसानों ने खोला मोर्चा

फतेहपुर में किसान नेता सहित क्षेत्रीय किसान धरने पर बैठे, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा धरना

फतेहपुर। फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बिजली उपकेन्द्र हथगांव में बिजली कटौती के चलते किसानों की फसल सूख रही हैं। इससे परेशान होकर आज बिजली उपकेंद्र हथगांव परिसर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान नेता सहित क्षेत्रीय किसान धरने पर बैठ गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती और अन्ना मवेशियों की समस्या को

लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रीय किसान संयुक्त रूप से समस्याओं के समाधान न होने तक बिजली उपकेंद्र हथगांव में किसान पंचायत के साथ धरने का आह्वान कर रहे हैं, जिसकी सूचना 3 दिन पहले किसान यूनियन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पप्पू सिंह अखरी वाले के द्वारा दी गई थी। धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला उपाध्यक्ष पप्पू सिंह ने बताया कि क्षेत्र के किसानों की समस्या के समाधान के लिए सक्षम अधिकारी को बुलाने की बात रखी गई है। जब तक किसानों के 5 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा यह धरना-प्रदर्शन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि बारिश हो नहीं रही और नहरों में पानी नहीं आ रहा। बिजली दो से तीन घंटे मिल रही है, जिस कारण से किसान अपने खेत में धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। जिन किसानों के खेत में धान की रोपाई हो चुकी है वह बिना पानी के सूख जा रहे हैं। अगर जिम्मेदार अधिकारियों ने किसानों के समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो सड़क मार्ग को जाम कर दिया जाएगा।

वन विभाग ने 1 ट्रक सागवान की लकड़ी पकड़ी

बलरामपुर। बलरामपुर के सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग के जनकपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ने एक ट्रक सागवान से लदी लकड़ी बरामद की है। वन विभाग के अधिकारी ट्रक में लदी लकड़ी की जांच कर रहे हैं। वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी की एक जंगल से अवैध सागौन की लकड़ी काटकर ट्रक द्वारा पचपेड़वा से लादकर बिक्री करने हेतु बाहर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम पहुंच गई और पचपेड़वा से ट्रक द्वारा लादकर लाई जा रही सागवान की लकड़ी को तुलसीपुर में पकड़ लिया। बताया जाता है कि इस ट्रक पर 170 बोटा सागवान की लकड़ी लदी है। डीएफओ डॉ. सेममरण एम ने मंगलवार को बताया की ठेकेदार द्वारा 17 पेड़ों के कटान की परमिट ली गई थी, लेकिन सूचना मिली है की परमिट से ज्यादा पेड़ों की कटान की गई है। ट्रक पर लदी लकड़ियों की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सोहेलवां वन क्षेत्र में वनों की अवैध कटान की लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं, जिस पर वन विभाग और पुलिस द्वारा समय-समय पर कार्रवाई भी की जाती रहती है।

शार्ट न्यूज

जुलाई में 1.65 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह

नयी दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह इस वर्ष जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है जो जुलाई 2022 के जीएसटी संग्रह की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्रालय ने आज यहां जारी बयान में कहा कि जीएसटी के प्रवाभी होने से लेकर जुलाई ऐसा पांचवां महीना रहा है जब जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। जून में जीएसटी संग्रह 161497 करोड़ रुपये रहा था। इस वर्ष अप्रैल में रिकार्ड 1.87 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रहित हुआ था जो अब तक का सर्वाधिक राजस्व था। इससे पहले पिछले वर्ष अप्रैल में यह राशि 167540 करोड़ रुपये रहा था। पिछले 16 महीने से जीएसटी राजस्व संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक बना हुआ है। मार्च 2023 में यह 160122 करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने आज यहां जीएसटी राजस्व संग्रह का आंकड़ा जारी किया जिसमें जुलाई 2023 में संग्रहित राजस्व 165105 करोड़ रुपये रहा है। इस वर्ष जुलाई में संग्रहित राजस्व में सीजीएसटी 29773 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 37623 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 85930 करोड़ रुपये रहा जिसमें आयात पर संग्रहित कर 41239 करोड़ रुपये शामिल है। उपकर संग्रह 11779 करोड़ रुपये रहा जिसमें आयात पर संग्रहित कर 840 करोड़ रुपये शामिल है।

जाति आधारित गणना पर रोक से उच्च न्यायालय का इंकार स्वागतयोग्य : माले

पटना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा-माले) के राज्य सचिव कुणाल ने पटना उच्च न्यायालय के जाति आधारित गणना को जारी रखने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे सामाजिक न्याय की घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को झटका लगा है। कुणाल ने कहा की वह तो चाहते हैं कि बिहार सहित पूरे देश में ही जाति आधारित गणना हो। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि भाजपा शुरू से ही जाति आधारित गणना की विरोधी रही है। उसके लोग इसे रूकवाने के लिए उच्च न्यायालय गए थे, लेकिन आज उच्च न्यायालय ने जाति गणना पर रोक से साफ इंकार कर दिया। भाकपा-माले के राज्य सचिव ने कहा कि यह और जरूरी इसलिए हो जाता है कि आज भी हमारे पास 1931 का ही डाटा है, जब देश में जाति गणना हुई थी। उसी आंकड़े के आधार पर सरकारी योजनाएं बनती हैं। दलित-पिछड़ी जातियों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं को अद्यतन करने, आरक्षण को तर्कसंगत बनाने तथा सामाजिक स्तर में सुधार के लिए जाति गणना बेहद जरूरी है ताकि हमारे पास सही-सही आंकड़े हो। उन्होंने कहा कि, हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अब तक की हुई गणना में जो भी विसंगतियां उभरकर सामने आई हैं, उसे ठीक करने पर सरकार गंभीरता पूर्वक काम करेगी।

जुलाई में बिजली की खपत 8.4 प्रतिशत बढ़कर 139 बिलियन यूनिट हुई

नई दिल्ली। देश में बिजली की खपत इस वर्ष जुलाई में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 8.4 प्रतिशत बढ़कर 139 अरब यूनिट हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एक साल पहले बिजली की खपत 128.25 बिलियन यूनिट (बीयू) थी, जो जुलाई 2021 में 123.72 बीयू से अधिक थी। बिजली की अधिकतम मांग जो एक दिन में सबसे अधिक आपूर्ति है, जुलाई 2023 में बढ़कर 208.82 गीगावॉट हो गई। जुलाई 2022 में पीक पावर सप्लाई 190.35 गीगावॉट और जुलाई 2021 में 200.53 गीगावॉट थी। बिजली मंत्रालय ने गर्मी के मौसम में देश की बिजली मांग 229 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान लगाया था। लेकिन बेमौसम बारिश के कारण इस साल अप्रैल-मई में मांग अनुमानित स्तर तक नहीं पहुंच पाई। देश में व्यापक बारिश के कारण इस साल मार्च, अप्रैल, मई और जून में बिजली की खपत पर असर पड़ा। विशेषज्ञों ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई और जून में बेमौसम बारिश ने देश में बिजली की खपत को प्रभावित किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस साल जून में बिजली खपत की वृद्धि उतनी खराब नहीं थी और जुलाई में इसमें काफी सुधार हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश ने बिजली की मांग को कम कर दिया क्योंकि लोगों ने पिछले वर्ष की तुलना में कम शीतलन उपकरणों का उपयोग किया।

62 प्रतिशत इंट्री लेवल कर्मचारियों को इस साल नहीं मिली कोई वेतन वृद्धि

नई दिल्ली। जॉब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फाउंडइट, जिसे पहले मॉन्स्टर एपीएसी और एमई के नाम से जाना जाता था ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में खुलासा किया कि भारत में 60 प्रतिशत से अधिक एंट्री लेवल कर्मचारियों को इस साल अप्रेज सीजन में वेतन वृद्धि नहीं मिली। रिपोर्ट के एक अंश में कहा गया है, प्रवेश स्तर के पेशेवरों (0-3 साल के अनुभव वालों) के लिए वेतन वृद्धि में एक दिलचस्प बात सामने आई है, 62 प्रतिशत लोगों ने दावा किया कि उन्हें इस साल कोई मूल्यांकन (अप्रेजल) नहीं मिला। जबकि दस प्रतिशत कर्मियों ने माना कि उन्हें 5-10 से प्रतिशत की वेतन वृद्धि मिली, जबकि 9 प्रतिशत को 0-5 प्रतिशत वेतन वृद्धि मिली। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां पारिश्रमिक में मौद्रिक वृद्धि के अलावा कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर भी विचार कर रही हैं। फाउंडइट के सीईओ शेखर गरिसा के अनुसार, फाउंडइट अप्रेजल ट्रेंड्स रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनियां वेतन वृद्धि के लिए अतिरिक्त और वैकल्पिक उपायों पर भी विचार कर रही हैं, जैसे कि ईएसओपी, बोनस और पदोन्नति। रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्यांकन प्राप्त नहीं करने वाले 49 प्रतिशत कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) और बोनस के साथ प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा, बिना वेतन वृद्धि वाले 20 प्रतिशत लोगों को पदोन्नति की पेशकश की गई, जो दर्शाता है कि करियर के विकास के अवसरों को स्वतंत्र रूप से तत्काल वित्तीय पुरस्कारों के जरिए मुहैया कराया गया।

88 प्रतिशत नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौटे

नई दिल्ली। देश में 88 प्रतिशत 2000 के नोट बैकों में वापस आ चुके हैं। 31 जुलाई 2023 तक बाजार में अब महज 42,000 करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही बचे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि 31 जुलाई 2023 तक 3.14 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। अब महज 42 हजार करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही बाजार में चलन में है। आरबीआई के अनुसार 19 मई 2023 को बाजार में चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोटों में से 88 प्रतिशत नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। 31 मार्च 2023 को बाजार में 3.62 लाख करोड़ रुपये के दो हजार के नोट बाजार में चलन में थे। 19 मई 2023 को यह घटकर 3.56 लाख करोड़ रुपये रह गए थे। इसी दिन आरबीआई ने दो हजार रुपये के नोटों को बाजार से वापस लेने का फैसला किया था।

कॉमर्शियल सिलेंडर 100 रुपए सस्ता

नई दिल्ली। 1 अगस्त से देशभर में 4 बदलाव हुए हैं। अब आईटीआर फाइल करने के लिए लेट फीस चुकानी होगी। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 99.75 रुपए घट गए हैं। सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। इसके अलावा तेल कंपनियों ने एटीएफ की कीमतों में 7728 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इससे हवाई सफर महंगाई हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 31 जुलाई को शाम 6 बजे तक 6.50 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके थे। इनमें से लगभग 36.91 लाख आईटीआर सिर्फ आखिरी दिन दाखिल किए गए। अगर आपने यह डेडलाइन मिस कर दी है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए अब फाइन देना होगा। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।

पावरग्रिड के कमजोर तिमाही परिणाम से गिरा शेयर बाजार

मुंबई। विश्व बाज़ार के नकारात्मक रुझान और स्थानीय स्तर पर पावर ग्रिड के कमजोर तिमाही परिणाम से उसके शेयरों में पांच प्रतिशत की आई गिरावट के दबाव में आज सेन्सेक्स और निफ़्टी गिर गए।

बीएसई का संवेदी सूचकांक सेन्सेक्स 68.36 अंक गिरकर 66,459.31 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ़्टी 20.25 अंक फिसलकर 19,733.55 अंक रह गया। इसी तरह बीएसई का मिडकैप 0.23 प्रतिशत उतरकर 30,349.34 अंक जबकि स्मॉलकैप 0.50 प्रतिशत की तेज़ी लेकर 35,177.85 अंक पर पहुंच गया।

इस दौरान बीएसई में कुल 3728 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2068 में लिवाली जबकि 1492 में बिकवाली हुई वहीं 168 में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह निफ़्टी की 23 कम्पनियाँ हरे जबकि 26 में बिकवाली हुई वहीं दो के भाव स्थिर रहे।

पावर ग्रिड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफ़ा 5.9 प्रतिशत गिर गया, जिससे आज उसके शेयर 5.36 प्रतिशत लुढ़क गए। इसके साथ ही रिलायंस, मारुति और एसबीआई समेत 15 दिग्गज कम्पनियों में भी जमकर बिकवाली हुई और शेयर बाज़ार दबाव में आ गया।

बीएसई के 13 समूहों में बिकवाली हुई। इस दौरान सीडी 0.10, एफएमसीजी 0.21, वित्तीय सेवाएं 0.02, हेल्थकेयर 0.33, इंडस्ट्रियल 0.29, यूटिलिटीज 0.06, ऑटो 0.25, बैंकिंग 0.20, कैपिटल गुड 0.40, तेल एवं गैस 0.17, पावर 0.32 और रियलटी समूह के शेयर 1.78 प्रतिशत गिर गए।

विदेशी बाज़ारों में गिरावट का रुख़ रहा। इस दौरान ब्रिटेन का एफ टी एस ई 0.58, जर्मनी का डैक्स 0.95, हांकांग का हैंगसेंग 0.34 और चीन का शंघाई कंपोज़िट 0.01 प्रतिशत उतर गया जबकि जापान के निक्केई में 0.92 प्रतिशत की तेज़ी रही।

कारोबार की शुरुआत में सेन्सेक्स पांच अंक की मामूली बढ़त लेकर 66,532.98 अंक पर सपाट खुला और दमदार लिवली की बदौलत थोड़ी देर बाद ही 66,658.12 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। लेकिन बिकवाली होने से यह दोपहर में 66,388.26 अंक के निचले स्तर तक लुढ़क गया। संभलने की तमाम कोशिशों के बावजूद अंत में पिछले दिवस के 66,527.67 अंक के मुक़ाबले 0.10 प्रतिशत उतरकर 66,459.31 अंक पर आ गया।

निफ़्टी भी 30 अंक की बढ़ोतरी लेकर 19,784.00 अंक पर खुला और सत्र के दौरान 19,795.60 अंक के उच्चतम जबकि 19,704.60 अंक के निचले स्तर पर भी रहा। अंत में पिछले सत्र के 19,753.80 अंक की तुलना में 0.10 प्रतिशत टूटकर 19,733.55 अंक पर आ गया।

इस दौरान सेन्सेक्स की नुक़सान उठाने वाली कम्पनियों में पावर ग्रिड 5.36, बजाज फ़िनसर्व 1.62, इंडसइंड बैंक 1.45, रिलायंस 1.38, एसबीआई 1.35, मारुति 1.06, एशिअन पेंट 0.98, एलटी 0.51, बजाज फ़ाइनैन्स 0.49, हिंदुस्तान यूनीलिवर 0.40, अल्ट्रा सिम्को 0.40, कोटक बैंक 0.34, आईसीआईसीआई बैंक 0.30, आईटीसी 0.18 और टाटा मोटर 0.12 प्रतिशत शामिल रही।

वहीं, एनटीपीसी 3.07, टेक महिंद्रा 2.50, एचसीएल टेक 1.88, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.17, टी सी एस 0.87, इनफ़ोसिस 0.75, ऐक्सिस बैंक 0.68, एच डी एफ सी बैंक 0.64, जे एस डब्लू एस स्टील 0.49, विप्रो 0.46, नेस्ले इंडिया 0.24, भारती एयरटेल 0.15, सन फ़ार्मा 0.06 और टाटा स्टील ने 0.04 प्रतिशत का मुनाफ़ा कमाया।

'श्री अन्न' को नए सिरे से बढ़ावा देगी योगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जनता को 'पुष्टाहार से लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने अब मिलेट्स यानी 'श्री अन्न' के प्रति जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित 'उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम' के माध्यम से श्री अन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके अंतर्गत न केवल मिलेट्स से बनने वाली रेसिपीज को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि उनके बारे में जागरूकता भी फैलाई जाएगी। इस कार्य योजना के अंतर्गत अब तक मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए गए, मगर अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे प्रदेश वृहद स्तर पर आमजन द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार का सहारा लिया जाएगा। न केवल प्रदेश के सभी जिलों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा बल्कि इसे छात्रों के करिकुलम में भी शामिल किया जाएगा। हालांकि, उससे पहले शिक्षकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता होगी और इसी बात को ध्यान में रखकर प्रदेश भर में अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्य को भी प्रारंभ किए जाने की तैयारी कर ली गई है।

उल्लेखनीय है कि भारत विश्व में मिलेट्स एक्सपोर्ट्स के लिहाज से दूसरे पायदान पर है तथा केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है कि भारत को आगामी वर्षों में 'नंबर वन मिलेट्स एक्सपोर्टर कंट्री' के रूप में जाना जाए। ऐसे में, देश के फूड बास्केट के तौर पर विख्यात प्रदेश भी एक बड़ी और सकरात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर सीएम योगी की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर को मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम को आच्छादित करने की विस्तृत कार्य योजना को हरी झंडी दे दी गई है।

फरवरी से अभियान ने पकड़ी रफ्तार

उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग द्वारा 01 फरवरी, 2023 से प्रदेश भर में मिलेट्स की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का व्यापक अभियान चलाया गया जिसमें उन्हें मुफ्त बीज मिनीकिट उपलब्ध कराई गई। समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के जरिए भी मिलेट्स के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेट्स आधारित संस्करण इकाई स्थापित किए जाने को भी प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, नई विस्तृत कार्य योजना के अंतर्गत अब जिला स्तर पर मिलेट्स रेसीपी विकास, उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम, स्कूल करीकुलम व अध्यापकों के व्यापक प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मिलेट्स को बतौर वैल्यू ऐडेड व वैल्यू प्रेस्ड प्रोडक्ट्स के तौर पर पेश किया जाएगा और इसके लिए मिलेट्स एफपीओ की देखरेख में मेलों का आयोजन किया जाएगा।

छात्र-छात्राओं में होगा जागरूकता का प्रसार

मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए जिन मेलों को प्रदेश के हर जिले में आयोजित किए जाने की योजना है, उनमें मुख्य तौर पर स्कूली छात्र-छात्राओं, अभिभआवकों व शिक्षकों को जागरूक किया जाएगा। मिलेट्स के गुणों के प्रति जागरूकता लाने के लिए शैक्षणिक करिकुलम में भी इसे शामिल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।

वहीं, शुरुआती स्तर पर प्रदेश भर में 200 शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हीं के माध्यम से प्रदेश के अन्य शिक्षकों को भी मिलेट्स जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और श्री अन्न के उपयोग, इससे जुड़े मिथकों को दूर करने व व्यापक जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए ट्रेंड किया जाएगा। में मिलेट्स को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा तथा मिलेट्स को पहचानना तथा उसके पोषक तत्वों को लेकर निबंध लेखन, क्विज, प्रोजेक्ट वर्क आदि का आयोजन भी सुनिश्चित किए जाने की योजना है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी देगी कार्य योजना को अंजाम

प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी इन कार्यक्रमों को लागू कराए जाने के उत्तरदायी होंगे और सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्य विकास अधिकारी बतौर उपाध्यक्ष, उप कृषि निदेशक बतौर सचिव व बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मिलेट्स के कार्यक्रम एफपीओ व जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रगतिशील कृषक बतौर सदस्य प्रतिभाग करेंगे। इन सभी गतिविधियों पर खर्च के लिए बजट उप कृषि निदेशक द्वारा पास किया जाएगा जो कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के अनुमोदन के बाद होगा।

दादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा सोलर प्लांट

नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के दादरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 केडब्ल्यूपी क्षमता वाली सौर ऊर्जा इकाई लगायी गयी है।

इस सौर ऊर्जा इकाई को वोल्वो कार इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिजली की जरूरतों को पूरा करेगी, साथ ही किसी भी असंभावित परिस्थिति के चलते बिजली नहीं रहने पर भी सामान्य कामकाज का सुचारू तरीके से संचालन सुनिश्चित होगा। इस केन्द्र में प्रतिदिन 700 से अधिक मरीज आते हैं।

कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि उद्योग संगठन एसोचैम के साथ मिलकर उसने यह संयंत्र लगाया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक ज्योति मल्होत्रा ने कहा, वॉल्वो के लिए सस्टेनेबिलिटी सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम समुदायों के लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें भी सस्टेनेबिलिटी को शामिल करते हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली उपलब्ध कराना, सही मायने में इन केंद्रों द्वारा एक बड़ी ग्रामीण आबादी को दी जाने वाली सेवाओं की कुशलता बढ़ाने का स्थायी और सबसे किफायती तरीका है। दादरी के सीएचसी में सोलर प्लांट लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि इस स्वास्थ्य केंद्र को नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली प्राप्त हो, और इस तरह बिजली की खपत पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा। इससे तैयार होने वाली अतिरिक्त हरित बिजली को ग्रिड में भेजा जाएगा, और इस तरह हम सस्टेनेबिलिटी में पहले की तुलना में अधिक योगदान दे पाएंगे।

एसोचैम के महासचिव और एएफसीएसआर के ट्रस्टी दीपक सूद ने कहा, एसोचैम भारतीय उद्योग के साथ मिलकर काम करता है, ताकि समुदाय के लोग प्रगति के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। सरकार द्वारा स्थापित इन स्वास्थ्य केंद्रों से देश भर के सभी समुदायों को लाभ मिलता है, साथ ही उद्योग जगत के एक प्रमुख निकाय के रूप में एसोचैम अपने सदस्यों को इन केंद्रों को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिसमें उपकरणों से लेकर इससे संबंधित हर प्रकार की सहायता शामिल है। दादरी में सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने में वॉल्वो कार्स इंडिया के साथ इस साझेदारी पर हमें गर्व का अनुभव हो रहा है।

इस स्वास्थ केंद्र को बिजली के भरोसेमंद बैकअप सिस्टम की जरूरत थी, और यह पहल इसी आवश्यकता को पूरा करेगी।

जेक्यूआर स्पोर्ट्स ने नया स्नीकर कलेक्शन 'स्टाइल' किया लॉन्च

नयी दिल्ली। स्पोर्ट्स और स्नीकर फुटवियर बनाने वाली अग्रणी कंपनी जेक्यूआर स्पोर्ट्स ने नया स्नीकर कलेक्शन 'स्टाइल' लॉन्च किया है।

कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि स्नीकर के शौकीनों एवं फैशन में आने रहने वाले लोगों को आकर्षित करने के लिये डिजाइन किया गया यह नया कलेक्शन अत्याधुनिक स्टाइल, जबर्दस्त कम्फर्ट और बेजोड़ परफॉर्मेंस का एक परफेक्ट संयोजन है।

स्टाइल कलेक्शन में अभिनव डिजाइनों में रेगुलर क्लासिक स्नीकर्स, मिड-एंकल स्नीकर्स, आदि शामिल हैं। जेक्यूआर स्पोर्ट्स के सीईओ रिंकू गर्ग ने कहा, हम समझते हैं कि स्नीकर्स सिर्फ फुटवियर से कहीं बढ़कर हो गये हैं और वे अब निजी स्टाइल तथा अपनी अभिव्यक्ति का प्रतीक हैं।

अपने नये कलेक्शन के साथ हम कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकले हैं और हमने डिजाइन, कम्फर्ट तथा परफॉर्मेंस के लिये अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया है, ताकि स्नीकर के शौकीनों को सचमुच में एक बेजोड़ अनुभव दिया जा सके।

एम्स में जैक्सन ग्रुप ने लगाया नौ किलोवॉट का सोलर पैनल

नयी दिल्ली। ऊर्जा एवं अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनी जैक्सन ग्रुप ने दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साथ एक साझेदारी की है जिसके तहत एम्स के निदेशक के बंगले पर नौ किलोवॉट का सोलर पैनल लगाया गया है।

कंपनी ने इस साझेदारी के तहत पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल उपाय अपनाते हुए ये पैनल लगाए हैं। जैक्सन ग्रुप की सीएसआर इकाई जैक्सन वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में 9 किलोवॉट का ये प्रोजेक्ट लगाया गया है जिससे हर साल 13,140 यूनिट बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है। इससे खपत की 100 फीसदी बिजली तैयार हो जाएगी। कंपनी ने अपने सबसे नए और सबसे बेहतर हेलिया सीरीज के सोलर पैनल लगाए हैं, जो हाफ कट मोनोपीईआरसी सोलर सेल की ए प्लस कैटेगरी पर बनाए गए हैं और कम एलसीओई प्रोवाइड करते हैं।

एम्स के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास और आईआरईडीए के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पी के दास ने आज इसका उद्घाटन किया। जैक्सन ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समीर गुप्ता ने इस अवसर पर कहा, हमें इस परियोजना के लिए एम्स, दिल्ली के साथ सहयोग करके खुशी हो रही है। एक डायवर्स ऊर्जा कंपनी के रूप में जैक्सन नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न समाधानों के माध्यम से पूरे देश में नेट जीरो मिशन का समर्थन करने के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है और एम्स के साथ हमारी साझेदारी यही प्रतिबद्धता दिखाती है। हम एम्स को उनकी हरित यात्रा शुरू करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के अभियान में अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों को शामिल होने के लिए प्रेरित करने वाला उदाहरण स्थापित करने की बधाई देते हैं।

डॉ श्रीनिवास ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा, पर्यावरण से जुड़े हमारे उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। हम न केवल अपने परिचालन को बेहतर बनाने में, बल्कि बड़े पैमाने पर पर्यावरण के हित में योगदान देने के लिए भी ग्रीन एनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान रहे हैं। यह सहयोग हेल्थकेयर के टिकाऊ प्रचलनों को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है और हमें उम्मीद है कि यह अन्य संस्थानों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।इस परियोजना के साथ जैक्सन ने हेल्थकेयर के इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ एक और बड़ा लैंडमार्क स्थापित किया है। इससे पहले जैक्सन एम्स के भुवनेश्वर और ऋषिकेश कैंपस के लिए पावर बैक-अप सॉल्यूशन और ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है।

दूसरी तिमाही में देश में सोने की मांग में सात प्रतिशत की कमी

नयी दिल्ली। सोने की कीमतों में तेजी आने के साथ ही वैश्विक स्तर की अनिश्चितता की स्थिति के कारण लोगों के अधिक व्यय करने से बचने की वजह से देश में दूसरी तिमाही में पीली धातु की मांग में सात प्रतिशत की कमी रही है और अप्रैल से जून की इस तिमाही में भारत में 158.1 टन सोने की बिक्री हुयी है।

विश्व स्वर्ण परिषद की आज जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है। इसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष की दूसरी तिमाही में देश में 170.7 टन सोने की बिक्री हुयी थी जबकि इस वर्ष की समान अवधि में यह घटकर 158.1 टन रह गया। इसमें कहा गया है कि पहली छमाही में देश में कुल मिलाकर 271 टन सोने की मांग रही है और यदि मानसून ने साथ दिया तथा त्योहारी सीजन विशेषकर दिवाली के समय मांग आयी तो इस वर्ष भारत में 650 से 750 टन सोना बिक सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि कीमतों में हुय वृद्धि के कारण दूसरी तिमाही में 82530 करोड़ रुपये का सोना बिका है जबकि वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 79270 करोड़ रुपये रहा है। इस वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत में कुल आभूषण की मांग 2022 की दूसरी तिमाही के 140.3 टन की तुलना में आठ प्रतिशत कम होकर 128.6 टन रही।श आभूषण की मांग का मूल्य 67,120 करोड़ रुपये था, जो 2022 की दूसरी तिमाही 65,140 करोड़ रुपये से 3 प्रतिशत की वृद्धि है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 की दूसरी तिमाही में कुल निवेश मांग 2022 की दूसरी तिमाही के 30.4 टन की तुलना में 3 प्रतिशत घटकर 29.5 टन रह गई।

2023 की दूसरी तिमाही में भारत में पुनर्चक्रित कुल सोना 37.6 टन था, जबकि 2022 की दूसरी तिमाही में 23.3 टन की तुलना में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2023 की दूसरी तिमाही में भारत में कुल सोने का आयात 209 टन था, जबकि 2022 की दूसरी तिमाही के 180.7 टन की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब देश में मोबाइलधारकों की संख्या में आ रही स्थिरता

नयी दिल्ली। देश में अब मोबाइलधारकों की संख्या में लगभग स्थिरता आने लगी है जबकि ब्राडबैंड कनेक्शन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। मई 2023 में देश में मोबाइल धारकों की कुल संख्या मामूली 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 114.32 करोड़ पर पहुंची है। इस दौरान मोबाइलधारकों और बेसिक टेलीफोन धारकों की कुल संख्या मामूली 0.004 प्रतिशत बढ़कर 117.25 करोड़ रही।

दूरसंचार नियामक ट्राई की ओर से आज जारी मई महीने के आंकड़े के अनुसार मई 2023 में देश में ब्रांडबैंड कनेक्शन धारकों की कुल संख्या 85.68 करोड़ रही है। इसमें से वायरलेस ब्राडबैंड कनेक्शनधारकों की संख्या 82.23 करोड़ और वायरलाइन ब्राडबैंड धारकों की संख्या 3.44 करोड़ रही है। मई महीने में कुल सक्रिय मोबाइलधारकों की संख्या 104.34 करोड़ रही है।

ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों से एक बात और पता चली है कि अब शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइलधारकों की संख्या बढ़ रही है। मई 2023 में शहरी क्षेत्रों में मोबाइल धारकों की संख्या 0.08 प्रतिशत कम होकर 62.62 करोड़ पर आ गयी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51.69 करोड़ पर पहुंच गयी।

इप आंकड़ों से यह भी पता चला है कि उपभोक्ता बड़े पैमाने पर अपने ऑपरेटर भी बदल रहे हैं क्योंकि मई 2023 में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी(एमएनपी) के लिए 1.14 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने आवेदन किये। अप्रैल 2023 तक एमएनपी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 83.06 करोड़ थी जो मई 2023 में बढ़कर 84.21 करोड़ हो गयी।

मई 2023 में दूरसंचार ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी के मामले में रिलायंस जियो 51.96 प्रतिशत के साथ अव्वल रही है। इस मामले में 28.78 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ भारती एयरटेल दूसरे स्थान पर और 14.42 प्रतिशत शेयर के साथ वोडाफोन आइडिया तीसरे स्थान पर रही है।

इंडिया फर्स्ट लाइफ ने गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स योजना की लॉन्च

नयी दिल्ली। इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक नए उत्पाद - इंडिया फर्स्ट लाइफ गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स योजना को लांच किया है।

कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना पॉलिसी धारकों को नियमित दीर्घकालिक आय विकल्प प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।यह एक विस्तारित अवधि का बीमा-आधारित बचत बीमा है जो 30 साल और 40 साल की पॉलिसी अवधि के लिए 6 साल, 8 साल और 10 साल की लचीली प्रीमियम भुगतान शर्तें (पीपीटी) प्रदान करता है।

मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक प्रीमियम भुगतान विकल्पों के साथ यह योजना ग्राहकों के लिए दूसरी व अतिरिक्त आय बनाने का एक सुविधाजनक विकल्प है। कंपनी के डिप्टी सीईओ रुषभ गांधी ने कहा- पारंपरिक बीमा से परे जाकर यह योजना हमारे ग्राहकों को सशक्त बनाएगा। उनकी आवश्यकता के अनुसार दीर्घकालिक आय की योजना बनाई। अन्य योजनाओं के विपरीत जहां कुछ वर्षों के बाद रिटर्न प्राप्त होता है, वहा इस योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि कोई व्यक्ति पहले महीने के अंत से ही भविष्य की आय प्राप्त करने की प्लानिंग बना सकता है।

ईज़मायट्रिप करेगी तीन कंपनियों का अधिग्रहण

नयी दिल्ली। ऑनलाइन ट्रैवेल टेक प्लेटफार्म ईजमायट्रिप डॉटकॉम ने भारत में स्थापित तीन प्रमुख ट्रैवेल कंपनियों गाइडलाइन ट्रैवेल्स हॉलीडेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, ट्रिपशॉप ट्रैवेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर और डूक ट्रैवेल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के नियंत्रक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है।

शार्ट न्यूज

पाकिस्तान हॉकी टीम भारत पहुंची, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में लेगी हिस्सा

नई दिल्ली। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम सोमवार (एक अगस्त) को अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 2011 से हर साल एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा किया जाता है। इसमें एशिया की शीर्ष छह हॉकी टीमें शामिल होती हैं। यह टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन प्रारूप में होता है। इस बार चेन्नई को इसकी मेजबानी मिली है। वहां तीन से 12 अगस्त तक यह टूर्नामेंट चलेगा। इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से सबसे सफल टीमें हैं। दोनों ने तीन-तीन बार खिताब पर कब्जा किया है। भारत 2011 और 2016 में जीता है। वहीं, पाकिस्तान ने 2012 और 2013 में जीत हासिल की थी। 2018 में दोनों टीमें संयुक्त विजेता बनी थीं और पिछली बार 2021 में दक्षिण कोरिया ने खिताब पर कब्जा किया था। यह पहला अवसर है जब भारत टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इस बार भारत-पाकिस्तान के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलयेशिया की टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच मुहम्मद सकलैन ने कहा, टीम एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए चेन्नई जा रही है और पूरे एशिया से टीमें टूर्नामेंट में भाग लेंगी। खेल के माध्यम से हम अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की उम्मीद करते हैं।

मोरक्को के खिलाफ मैच के लिए दिग्विजय भारतीय टीम में, बोपन्ना खेलेंगे अंतिम डेविस कप टाई

नई दिल्ली। दिग्विजय प्रताप सिंह को मोरक्को के खिलाफ लखनऊ में होने वाले डेविस कप टेनिस विश्व ग्रुप दो के मुकाबले के लिए भारत की छह सदस्यीय टीम में चुना गया है। लखनऊ में 16 और 17 सितंबर को होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम में सुमित नागल, शशिकुमार मुकुंद, युकी भांबरी, रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना को भी चुना गया है। भारत के 43 साल के अनुभवी खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का यह अंतिम डेविस कप मुकाबला माना जा रहा है। युगल के इस विशेषज्ञ खिलाड़ी ने पिछले महीने कहा था कि वह अपने डेविस कप कॅरिअर को अब विराम देना चाहते हैं। रोहित राजपाल टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान होंगे। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कहा कि खिलाड़ियों का चयन उनकी रैंकिंग, उपलब्धता और मौजूदा फॉर्म के आधार पर किया गया है। टेनिस संघ ने कहा कि पांच खिलाड़ी साकेत माइनेनी, मनंद, मनीष सूर्यकुमार, करण सिंह और युवान नांदल मुख्य टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे। इस साल भारतीय टीम विश्व ग्रुप प्लेआफ में डेनमार्क से 2-3 से हारने के बाद विश्व ग्रुप-2 में पहुंच गई है।

जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच मे एक्सपेरिमेंट्स का बचाव किया

नई दिल्ली। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ त्रिनिदाद में 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलना है। टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए टीम मैनेजमेंट और कप्तान टीम को लेकर क्लियर है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कप्तान और टीम मैनेजमेंट को पता है कि वर्ल्ड कप में किसे मौका देना है। बदलाव को लेकर किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। उन्होंने आगे कहा, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में अलग-अलग खिलाड़ियों को अलग-अलग नंबर पर मौका देकर उनके प्रदर्शन को देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बदलाव किए और दूसरा वनडे हार गए। कई बार विकेट और परिस्थितियों के कारण भी ऐसा होता है। एक मैच में हार के बाद टीम मैनेजमेंट परेशान नहीं है। जडेजा ने कहा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले वेस्टइंडीज के साथ तीन वनडे मैचों की सीरीज अहम है। जहां हम अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं और उनकी क्षमता को परख सकते हैं। बड़े टूर्नामेंट में हम अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन के साथ ही उतरेंगे। दूसरे वनडे में अक्षर पटेल को नंबर -4 पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया है। वह भी टीम की प्लानिंग का हिस्सा था।

आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान

मुंबई। 18 अगस्त से शुरू हो रहे आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। करीब एक साल बाद चोट से वापसी कर रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पंड्या जैसे सभी सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है। यह सीरीज टीम इंडिया के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे हैं। भारतीय टीम को अगले महीने एशिया कप और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे में बुमराह की फॉर्म के साथ वापसी होती है तो टीम मजबूत होगी। भारतीय सिलेक्टर्स ने आयरलैंड दौरे के लिए कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पंड्या जैसे लगभग सभी सीनियर्स को आराम दिया है, जबकि तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा जैसे आईपीएल स्टार्स को टीम में मौका दिया गया है। इन सभी ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था। जसप्रीत बुमराह करीब एक साल के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। वे पीठ की चोट के बाद एनसीए में रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे थे। बुमराह ने न्यूजीलैंड में अपनी बैक सर्जरी भी कराई थी। बुमराह ने आखिरी मुकाबला 25 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में खेला था।

ट्विटर ने मुख्यालय में लगा नया 'एक्स' लोगो हटाया

वाशिंगटन। ट्विटर ने अमेरिका में कैलीफोर्निया प्रांत के सैन फ्रांसिस्को स्थित अपने मुख्यालय की इमारत के ऊपर से बिना अनुमति के लगाए गए 'एक्स' लोगो को हटा दिया है। एनपीआर न्यूज ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को के भवन निरीक्षण विभाग को इस लोगो को लेकर संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित 24 शिकायतें मिली थी। सैन फ्रांसिस्को बिल्डिंग इंस्पेक्शन विभाग के प्रवक्ता पैट्रिक हन्नान ने कहा कि बिना अनुमति स्थापना के लिए संपत्ति के मालिक से शुल्क का आकलन किया जाएगा। यह शुल्क संरचना की स्थापना और हटाने के लिए इमारत परमिट के लिए होगा। भवन निरीक्षण विभाग और योजना विभाग की जांच की लागत को कवर करने के लिए होगा। पिछले सप्ताह, ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो बदलकर 'एक्स' कर दिया। शुक्रवार को एक ट्वीट में श्री मस्क ने एक के बाद एक कंपनियों के चले जाने के बावजूद शहर को कभी नहीं छोड़ने की कसम खाई।

अमेरिका ने की बंगलादेश में हुई हिंसा की निंदा

ढाका। अमेरिका ने बंगलादेश में जारी राजनीतिक हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका की ओर से यह चिंता बंगलादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) की स्थायी समित के सदस्य गायेश्वर चंद्र रॉय पर हुए हमले को लेकर व्यक्त की गयी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने स्थानीय समय के अनुसार सोमवार को नियमित संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम हिंसक कार्रवाई की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच तथा अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की बेवसाइट पर इस संवाददाता सम्मेलन को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पत्रकार ने श्री मिलर से सवाल किया कि बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर लाखों लोगों ने ढाका में प्रदर्शन किया है। स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस दौरान पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने शनिवार को शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों तथा विपक्षी दल के नेताओं पर बर्बर तरीके से हमला किया। इस हमले में विपक्ष के शीर्ष नेता रॉय के साथ सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। विपक्ष के खिलाफ बढ़ती पुलिस की बर्बरता और इस मामले पर स्पष्ट रूप से सरकार के सख्त रुख को देखते हुए आप स्थिति का आकलन कैसे करते हैं?

चौथी एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी जीतने चेन्नई पहुंची भारतीय टीम

चेन्नई। बहुप्रतीक्षित हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में हिस्सा लेने के लिये भारतीय पुरुष हॉकी टीम मंगलवार सुबह यहां चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए प्रशंसकों ने भारतीय टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया।

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने चेन्नई आगमन पर कहा, मुझे लगता है कि हमने स्पेन में हाल ही में संपन्न चार देशों के टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 10 दिनों में हमने कुछ अच्छे विरोधियों का सामना किया और उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। हमने वैसे ही खेलना शुरू कर दिया है जैसे हम खेलना पसंद करते हैं।

उन्होंने कहा, इसके अलावा, हमने अपने हालिया मैचों में अपने खेल में कुछ सामरिक बदलाव किये हैं और अब हम एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें लागू करने का लक्ष्य रखेंगे। हम इस टूर्नामेंट को एशियाई खेलों की तैयारी के लिये इस्तेमाल करेंगे।

कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम कठोर प्रशिक्षण, रणनीतिक योजना और मजबूत टीम सौहार्द के साथ हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के लिये तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में पाकिस्तान के साथ सबसे सफल टीम है। दोनों देशों ने तीन-तीन बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और घरेलू सरज़मीन पर खेलते हुए हरमनप्रीत की टीम चौथी बार खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी।

भारतीय टीम तीन अगस्त को चीन के विरुद्ध अपना अभियान शुरू करेगी। इसके अलावा मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम पर लीग चरण में भारत का सामना जापान, कोरिया, पाकिस्तान और मलेशिया से भी होगा।

टूर्नामेंट प्रारूप के अनुसार, सभी छह टीमें राउंड-रॉबिन चरण में पांच मैच खेलेंगी और अंक तालिका की शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी।

इस बीच, भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह ने हाल के स्पेन दौरे पर टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, हमने स्पेन में अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर पिछले कुछ मैचों में जिसमें नीदरलैंड के खिलाफ 2-1 की जीत शामिल थी।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें खेल की गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हमें शुरुआत से ही ऐसा करने की जरूरत है ताकि हम खेल को सकारात्मक रूप से शुरू कर सकें।

हार्दिक ने कहा, मेरा मानना है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम अच्छी गुणवत्ता की होने के कारण एक कठिन चुनौती पेश करेगी। नतीजतन, हमारा दृष्टिकोण हर मुकाबले के लिये पूरी लगन से तैयारी करना होगा।

गौरतलब है कि भाग लेने वाली छह टीमों में से भारत, मलेशिया, जापान और कोरिया पहले ही मेजबान शहर चेन्नई पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान और चीना आज रात यहां पहुंचेंगे।

एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा लेगी भारतीय सॉफ्टबॉल टीम

नयी दिल्ली। चीन के हांग्झोउ में 23 सितंबर से होने वाले एशियाई खेलों में भारत पहली बार सॉफ्टबॉल के खेल में प्रतिस्पर्धा करेगा। भारतीय सॉफ्टबॉल संघ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एशियाड में हिस्सा लेने के लिये 16-सदस्यीय महिला टीम का चयन किया गया है। टीम चयन के लिये संभावितों की सूची के लिये परीक्षणों के बाद जून-जुलाई में दो सप्ताह के कोचिंग कैंप और परीक्षणों का आयोजन किया गया था। इस टीम में तीन अतिरिक्त खिलाड़ियों को भी चुना गया है। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन महाराष्ट्र ने भारतीय टीम में सबसे अधिक खिलाड़ियों का योगदान दिया। राज्य की पांच लड़कियों को राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है, जबकि केरल और पंजाब से क्रमश: तीन और दो खिलाड़ियों को चुना गया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से एक-एक खिलाड़ी ने टीम में जगह बनायी है। सॉफ्टबॉल संघ की अध्यक्ष नीतल नारंग ने कहा, एशियाई खेलों में भारतीय महिला सॉफ्टबॉल टीम की भागीदारी हमारे खिलाड़ियों के लिये चमकने और महाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ अपनी योग्यता साबित करने का अवसर है। इसके अलावा, यह उपलब्धि युवा एथलीटों, विशेषकर लड़कियों की भावी पीढ़ियों को सॉफ्टबॉल को पसंदीदा खेल के रूप में अपनाने के लिये प्रेरित करेगी। उल्लेखनीय है कि सॉफ्टबॉल पहली बार एशियाई खेलों में पदार्पण कर रहा है। भारत को एशियाई चैंपियनशिप में नियमित भागीदारी के आधार पर एशियाई खेलों में वाइल्ड कार्ड प्रवेश दिया गया है।

स्टार स्पोर्ट्स पर प्रसारित होगा महिला विश्व कप सुपर-16 चरण

मुंबई। भारत के प्रमुख खेल प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में जारी फीफा महिला विश्व कप 2023 के सुपर 16 चरण के प्रसारण अधिकार हासिल किये हैं। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्टार स्पोर्ट्स ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसके चैनलों पर टूर्नामेंट के सुपर-16 मुकाबलों के लाइव प्रसारण के अलावा ग्रुप चरण मुकाबलों की हाइलाइट्स भी दिखाई जायेंगी। प्रसारणकर्ता सेमीफाइनल और फाइनल के लिये क्षेत्रीय भाषा की कमेंट्री जोड़कर टूर्नामेंट के कवरेज को बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। स्टार स्पोर्ट्स के प्रवक्ता ने फीफा विश्व कप 2023 के साथ जुड़ाव पर कहा, फीफा महिला विश्व कप 2023 महिलाओं के खेल का अंतिम प्रदर्शन और उत्सव है। यह खेल में रुचि रखने वाली या आगे बढ़ने की इच्छुक लड़कियों के लिये प्रेरणा का प्रतीक है।

अगले दो महीने हमारे लिये महत्वपूर्ण

नयी दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में क्वालीफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अगले दो महीने टीम के लिये बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।

भारतीय टीम तीन अगस्त से 12 अगस्त के बीच एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी में हिस्सा लेकर अगले महीने चीन के हांग्झोउ में होने वाले एशियाई खेलों के लिये तैयारी करेगी। हरमनप्रीत की टीम अगर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करती है तो वह पेरिस ओलंपिक के लिये सीधा क्वालीफाई कर लेगी।

हरमनप्रीत ने हॉकी ते चर्चा पॉडकास्ट के नवीनतम एपिसोड पर कहा, अगले दो महीने हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में, हमारे पास हांग्झोउ एशियाई खेलों से पहले अच्छे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ खेलने का अवसर है। यह खिलाड़ियों के लिये अच्छा अनुभव होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी उन योजनाओं को क्रियान्वित करें जिन पर हमने काम किया है।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। संयोग से, चेन्नई हरमनप्रीत के लिये एक खास जगह है क्योंकि हॉकी इंडिया के तत्कालीन उच्च-प्रदर्शन निदेशक रोलेंट ओल्टमेंस ने उन्हें इसी शहर में हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान देखा था।

हरमनप्रीत ने कहा, मुझे याद है जब 2015 में जूनियर टीम की घोषणा होनी थी, मैं चेन्नई में राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेल रहा था, जिसे हमने जीता था। उस समय रोलेंट ओल्टमेंस मैच देखने के लिये वहां थे और हम हरियाणा के खिलाफ फाइनल खेल रहे थे। उसके बाद मुझे राष्ट्रीय शिविर के लिये बुलाया गया और फिर उसी वर्ष सीनियर वर्ग में पदार्पण किया। यह शहर मेरे दिल में एक विशेष जगह रखता है। मैं वहां वापस जाकर खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं।

इस बीच, हार्दिक सिंह ने 16 साल के बाद चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय मैचों की वापसी के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। आखिरी बार चेन्नई ने 2007 में एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 7-2 से हराकर 2007 पुरुष एशिया कप ट्रॉफी जीती थी।

हार्दिक ने कहा, हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में होना सभी के लिये विशेष है। जिस तरह दर्शकों ने राउरकेला और भुवनेश्वर में हमारा समर्थन किया, हमें उम्मीद है कि लोग यहां भी स्टेडियम आकर हमारा समर्थन करेंगे। मुझे चेन्नई में खेलने का इंतजार है।

चीन में डोकसुरी टाइफून से 11 की मौत, 27 लापता

बीजिंग में 70 साल में सबसे ज्यादा बारिश; 1 लाख 27 हजार लोगों को बचाया

बीजिंग। चीन में डोकसुरी टाइफून से 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 लोग लापता हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले 70 साल की सबसे ज्यादा 257.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले 1951 में इतनी तेज बारिश हुई थी। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू वर्कर्स ने अब तक 1 लाख 27 हजार लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पर भेजा है।

वहीं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जगह-जगह बाढ़ में फंसे लोगों को जल्द बचाने के निर्देश दिए हैं। चीन के फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक 13 जिलों के 44 हजार लोग फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं।

डोकसुरी से सड़कों पर बह रही गाड़ियां

चीन के स्टेट मीडिया हाउस सीसीटीवी ने बताया कि सेना ने चार हेलिकॉप्टर्स को बाढ़ के बीच फंसे लोगों को खाना, रेनकोट और कंबल देने के लिए भेजा है। सोमवार रात को 5 कस्बों में मोबाइल कम्यूनिकेशन तक ठप हो गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोज में तेज बहाव में सड़कों पर बहती गाड़ियों को देखा जा सकता है।

बीजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिन में उड़ान भरने वाली 70 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। वहीं, 2019 में शुरू हुए डाक्सिंग एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 300 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा गया है। सरकार ने 100 से ज्यादा रास्तों को बंद किया है।

डोकसुरी की तबाही से निपटने के लिए 334 करोड़ का फंड

पीपल्स डेली चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक डोकसुरी से मची तबाही से निपटने के लिए सरकार ने डिजास्टर रिलीफ फंड से 334 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है। वहीं, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान होने की संभावना है।

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के घरों से बाहर न निकल पाने के कारण सामान डेलीवर करने वाली कंपनियों के ऑर्डर में 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। चीन में 2012 में इतना तेज तूफान आया था। तब 80 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।

फिलिपींस में डोकसुरी से 36 लोगों की मौत

फिलिपींस में डोकसुरी तुफान में फंसी एक बोट पलटने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोट मनिला के पास तूफान में फंस गई थी। तेज बहाव के डर से सभी लोग बोट के एकतरफ हो गए जिससे वो पानी में डूब गई। वहीं, ताइवान में डोकसुरी के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई हैं।

चीन के हेबई प्रांत में मूसलाधार वर्षा से नौ लोगों की मौत, छह लापता

बीजिंग। चीन के उत्तरी प्रांत हेबेई में मंगलवार दोपहर तक मूसलाधार वर्षा के कारण नौ लोगों की मौत हो गई और छह लोग लापता हैं। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आज दोपहर तक हेबेई में मूसलाधारी बारिश से अचानक आई बाढ़ और तूफान से 87 काउंटियों और जिलों में से कुल 5,40,703 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि आपदा से हुए आर्थिक नुकसान की अभी भी जांच की जा रही है। अब तक, करीब 8,47,400 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्य प्रांतीय मौसम विज्ञान वेधशाला के अनुसार, शनिवार से हेबेई प्रांत में मूसलाधार बारिश जारी है। ज़ुओझोउ शहर हेबेई का एक क्षेत्र है जो बारिश के कारण आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक ज़ुओझोउ के 146 गांवों के कुल 1,33,913 लोग भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। अब तक ज़ुओझोउ के 124 गांवों से 1,25,100 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। ज़ुओझोउ ने बचाव टीमों के साथ सहयोग करने के लिए कुल 8,755 सदस्यों वाली 28 आपातकालीन बचाव टीमों की व्यवस्था की है, जिसमें ब्लू स्काई रेस्क्यू टीम, एक चीनी नागरिक राहत दल भी शामिल है। हेबेई का पड़ोसी शांक्सी प्रांत भी भारी बारिश से प्रभावित है। शाम सात बजे तक प्रांतीय बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत मुख्यालय के अनुसार, सोमवार को शांक्सी में कुल 42,211 लोगों को निकाला गया।

स्वीडन कुरान जलाने की प्रतिक्रिया पर ओआईसी की सिफारिशों की जांच करेगा

स्टॉकहोम। स्वीडन यूरोपीय देशों में कुरान जलाने के विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला के इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की ओर से अपनाए गए प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच करेगा। विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्टॉकहोम संगठन के साथ घनिष्ट सहयोग में रुचि रखता है। बिलस्ट्रॉम ने ट्वीट किया,57 ओआईसी सदस्य देशों ने अब एक प्रस्ताव अपनाया है जिसमें कई सिफारिशें हैं। हम इनकी सावधानीपूर्वक जांच करेंगे और ओआईसी और इसके सदस्य देशों के साथ अपनी महत्वपूर्ण बातचीत जारी रखेंगे। हमें घनिष्ट सहयोग में रुचि है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वीडिश सरकार ने देश में इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों से 'खुद को दूर रखने का स्पष्ट रुख' अपनाया। उन्होंने कहा कि स्वीडिश न्याय मंत्रालय देश के सार्वजनिक व्यवस्था कानून सहित कानूनी विश्लेषण कर रहा था। उल्लेखनीय है कि हाल के सप्ताहों में, डेनमार्क और स्वीडन में कुरान जलाने के कई प्रदर्शन हुए। गत 28 जून को, ईद उल-अज़हा छुट्टी के पहले दिन, स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में कुरान की एक प्रति जला दी गई। जनवरी में स्वीडन में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था।

एआई-संचालित चैटबॉट लॉन्च करने की योजना

कैलिफोर्निया। रूस में प्रतिबंधित सोशल मीडिया कम्पनी मेटा अगस्त में कृत्रिम बुद्धि-संचालित (एआई) चैटबॉट लॉन्च करने की योजना बना रहा है जो उपयोगकर्ताओं के जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए काल्पनिक पात्रों सहित विभिन्न व्यक्तित्वों के परिप्रेक्ष्य से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगा। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने मंगलवार को सूत्रों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। अखबार ने बताया कि चैटबॉट्स से एक नया खोज फ़ंक्शन प्रदान करने और अनुशंसित सामग्री पेश करने की उम्मीद की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी पहले ही नए फीचर का परीक्षण कर चुकी है, जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की नकल करता है और दूसरा सर्फर की शैली में यात्रा विकल्पों पर सलाह देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटा ने टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा के बीच उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने और बनाए रखने की कोशिश की और पिछले साल नवंबर में माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपनएआई अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा चैटजीपीटी लॉन्च करने के बाद से व्यापक एआई परिचय के अनुरूप होने का प्रयास किया।

यूक्रेनी कमांडो को खास ट्रेनिंग दे रही ब्रिटिश सेना

कीव/लंदन। रूस-यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के एक खास कमांडो ब्रिगेड को ट्रेनिंग दे रही है। इस ट्रेनिंग का मकसद रूसी सेना को अक्षम करना और दिसंबर में क्रिसमस से पहले रूस के कब्जे से क्रीमिया को वापस लेना है। इंग्लैंड के डार्टमूर में करीब 2 हजार यूक्रेनी सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं।

डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑपरेशन में समुद्र, हवा और जमीन से हमले की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना को रोकने के लिए एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को लंबी दूरी वाली नई मिसाइल भी देंगे, जिसका इस्तेमाल रूस के डिफेंस को तोड़ने के लिए किया जाएगा।

इससे पहले यूक्रेन के इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ किरिलो बुडानोव ने कहा था कि जल्द ही उनकी सेना क्रीमिया में दाखिल होगी। ये ट्रेनिंग डेवॉन के ओकेहैम्प्टन में मौजूद बैटल कैंप में हो रही है। यहां दूसरी किसी भी मिलिट्री यूनिट या आम जनता को जाने की इजाजत नहीं है। 42 कमांडो के रॉयल मरीन्स ट्रेनिंग देख रहे हैं। इसमें लंबी दूरी तक मार्च और रात में असली गोला-बारूद के साथ हमले की प्रैक्टिस हो रही है।

रूसी सेना को कमजोर करना चाहते हैं जेलेंस्की

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की देश से रूसी सेना को बाहर करना चाहते हैं।

उनके इसी लक्ष्य के तहत क्रीमिया को रूस से वापस लेने का टारगेट तय किया गया है। जेलेंस्की का मानना है कि उन्हें रूसी सेना पर लगातार हमले के साथ ही उसे कमजोर करने पर काम करना है। कर्च ब्रिज और क्रीमिया में लगातार ड्रोन हमले से रूसी की वहां पर पकड़ कमजोर पड़ सकती है।

ब्रिटेन के एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के मुताबिक, यूक्रेन की सेना जंग को अपने हिसाब से मोड़ पाए, इसके लिए उसे नाटो की रणनीति सिखानी होगी।

इसके बाद ही दुश्मनों पर हमले तेज किए जा सकते हैं। हालांकि, ये ट्रेनिंग कितनी सफल होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि यूक्रेनी सेना आने वाले चैलेंज का सामना कैसे करती है। 1954 में सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे में दिया था। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा और यूक्रेन और रूस अलग-अलग हुए तो दोनों देशों के बीच क्रीमिया को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। मार्च 2014 में क्रीमिया में रूसी शासन के पक्ष में 96 प्रतिशत मतदान हुआ था।

न्यूयॉर्क में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध

न्यूयॉर्क। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में टेकआउट ऑर्डर में एकल-उपयोग प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। नए नियमों के तहत शहर में रेस्तरां और डिलीवरी सेवाओं को टेकआउट और डिलीवरी ऑर्डर में प्लास्टिक के बर्तन, मसाला पैकेट, नैपकिन या अतिरिक्त कंटेनर प्रदान करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि ग्राहक उनके लिए न पूछें।इसका मतलब है कि रेस्तरां अब ग्राहक के अनुरोध के बिना स्वचालित रूप से प्लास्टिक के कंटेनर, चाकू और कांटे, मेयो के पैकेट, ड्रेसिंग, साथ ही केचप को शामिल नहीं करेंगे। एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे को कम करने के उद्देश्य से नए उपाय इस साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स द्वारा हस्ताक्षरित 'स्किप द स्टफ' कानून के तहत लागू हुए हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं... से मुद्रित एवं , ब्लाक नं 23 मकान नं 399 त्रिलोक पुरी दिल्ली -91 से प्रकाशित
संपादकः प्रवीण कुमार सिंह, आरएनआई नं. ·DELHIN/2011/38334, किसी भी विवाद के लिए पीआरबी एक्ट अंतर्गत उत्तरदायी, टेलीफोन नं.: 011-26700510/11 , ई-मेल : info@gauravshalibharat.com, समस्त विवादो का न्यायलय दिल्ली होगा

नई दिल्ली
बुधवार 02 अगस्त 2023
Www.gauravshalibharat.com

शार्ट न्यूज़

एनएचपीसी की कार्मिक ने वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स-2023,जर्मनी में कांस्य पदक जीता

जर्मनी में आयोजित 8वें वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स- 2023के दौरान सुश्री ए. नलिनी, वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त), एनएचपीसी पोडियम पर (दाएं से दूसरी) सुश्री अरुणाचलम नलिनी, वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त), एनएचपीसी ने 28 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक जर्मनी के कोलोन में आयोजित हो रहे 8वें वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स 2023 मेंबैडमिंटन महिला युगल में कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स 2023,विशेष रूप से बौनेपन वाले एथलीटों के लिए आयोजित होने वालीसबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। इसका लक्ष्य दुनिया भर के बौनेपन वाले एथलीटों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।सुश्री नलिनी एक फ़ाइनेंस प्रोफेशनल हैं और एनएचपीसी के सौर ऊर्जा परियोजना, तमिलनाडु में तैनात हैं। सुश्री नलिनी ने अपनी बहुविकलांगता (ओर्थोपीडिक और ड्वार्फ) के बावजूदविभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं।एनएचपीसी ने सुश्री नलिनी को इस 8वें वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स 2023में भाग लेने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है। एनएचपीसी हमेशा अपने कर्मचारियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है।

कांग्रेस ने राहुल शर्मा को बनाया सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफार्म का नेशनल कॉर्डिनेटर

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के पूर्व चेयरमैन राहुल शर्मा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, AICC ने सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफार्म का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। राहुल शर्मा दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं । इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया में लोकसभा कनवीनर, व चेयरमैन दिल्ली प्रदेश सोशल मीडिया के पद पर भी कार्य किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफार्म में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं जिनको अलग अलग राज्यों का इंचार्ज बनाया जाएगा और वहां संगठन को मजबूत बनाने का काम दिया जाएगा।

एक किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोनभद्र । शक्तिनगर पुलिस ने एक किलो 500 ग्राम अवैध नाजायज गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ0 यशवीर सिंह द्वारा जनपद में मादक पदार्थो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी पिपरी प्रदीप सिंह चंदेल के कुशल निर्देशन में शक्तिनगर थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश पाण्डेय के नेतृत्व में वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव द्वारा सोमवार को समय 19.30 बजे अभियुक्त अरविन्द भट्ट पुत्र स्व0 बृहस्पति भट्ट निवासी बलियरी थाना बैढ़न सिगरौली मध्य प्रदेश उम्र 20 वर्ष बलियानाला रेलवे पुलिया नं0 10 के पास बहद ग्राम चिल्काटाड़ थाना शक्तिनगर के पास से कुल एक किलो 500 ग्राम अवैध नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना शक्तिनगर पर एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 01 अगस्त 2023 को अभियुक्त उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। गिरफ्तार करने वाले टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव, का0 आदर्श शुक्ला, का0 अरविन्द कुमार व का0 केवल कुमार थाना शक्तिनगर शामिल रहें।

सीबीआई ने रिश्वतखोरी मामले में दो बैंक अधिकारियों को किया गिरफ्तार

नयी दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित रिश्वत मामले में उत्तर प्रदेश के बागपत में तैनात पंजाब नेशनल बैंक के एक शाखा प्रबंधक और फील्ड अधिकारी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने कहा कि शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर 31 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता का बागपत के पंजाब नेशनल बैंक में उसके और उसके दादा के नाम पर संयुक्त रूप से एक केसीसी खाता था। आगे कहा गया कि उक्त केसीसी खाते में 4.95 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और उसे बचत बैंक खाते में वितरित किया गया था। आरोप है कि उक्त बचत बैंक खाते की 50 हजार रुपये की राशि शाखा प्रबंधक ने रोक रखी थी। जब शिकायतकर्ता ने शाखा प्रबंधक और फील्ड अधिकारी से इसके बारे में पूछताछ की तो दोनों ने उक्त राशि जारी करने के लिए शुरुआत में 35,000 रुपये की कथित रिश्वत मांगी। जांच एजेंसी ने कहा कि बाद में रिश्वत की रकम घटाकर 25,000 रुपये कर दी गई। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपियों को उस समय पकड़ लिया जब वे शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 25,000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे।

देश में समृद्ध होते उड्डयन क्षेत्र की उत्तर प्रदेश बना पहचान : सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा- बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या में करें बढ़ोत्तरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में समृद्ध होते उड्डयन क्षेत्र की नई पहचान बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश में अभी तीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विस्तार हो इसके लिए प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या में वृद्धि करें एवं नागरिक सुविधाओं में विस्तार सुनिश्चित करें।

सीएम योगी ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की और प्रस्तुतिकरण देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-2017 के सापेक्ष छह साल में प्रदेश में

माल ढुलाई हुई चार गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-2017 में प्रदेश में माल ढुलाई जहां 5895 मीट्रिक टन थी, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 20, 813 मीट्रिक टन हो गई। यह वृद्धि काफी सराहनीय है। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2016-2017 में प्रदेश में एयर ट्रैफिक जहां 46,585 था। वहीं साल 2022-2023 में यह संख्या बढ़कर 82,615 हो गई है। हवाई उड़ानों के साथ-साथ यात्रियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-2017 के 59.97 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। वहीं 2022-2023 में 96.02 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही हवाई यात्रियों की संख्या को देखते हुए उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। सीएम योगी ने कहा कि दिव्य और भव्य कुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता नागरिक सुविधाओं में विस्तार करें। साथ ही प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता को तीन सौ से बढ़ाकर पांच सौ यात्रियों की करें। इसके अलावा प्रदेश में हेलीकॉप्टर की सुविधा को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर हो इसके लिए वहां पर आरआरटीएस या लाइट मेट्रो की व्यवस्था करें।

सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर एयरपोर्ट का त्रिपक्षीय सर्वे जुलाई में पूर्ण हो चुका है। इसके निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करें। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 17 हवाई पट्टी और हमारी आठ हवाई पट्टियों भारतीय वायु सेना अंतर्गत हैं। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती, आजमगढ़, चित्रकूट, अलीगढ़ में राज्य सरकार द्वारा कराए जा सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं, यह प्रगति सराहनीय है।

एम्स प्रशासन से वार्ता के बाद नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन खत्म

एजेंसी

ऋषिकेश। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नर्सिंग ऑफिसर्स की लंबित मांगों को लेकर बीते दिनों से चला आ रहा गतिरोध मंगलवार को समाप्त हो गया। एम्स प्रशासन व नर्सिंग प्रतिनिधियों के मध्य हुई वार्ता के बाद, अधिकांश बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद सहमति बन गई। इसके बाद नर्सिंग कर्मियों ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया है।

एम्स द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसरों का गतिरोध एम्स प्रशासन से वार्ता के बाद समाप्त हो गया है। सभी बिंदुओं पर एम्स प्रशासन के नुमाइंदों व नर्सिंग प्रतिनिधियों के मध्य विचार विमर्श के बाद सकारात्मक निर्णय लिए गए।

ऑफिसर्स की सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विमर्श किया गया। दो दौर की वार्ता के बाद कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बताया गया कि पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर एम्स प्रशासनिक टिप्पणी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजेगा और मंत्रालय की सलाह के उपरांत उक्त बिंदुओं पर निर्णय लिया जाएगा। इनमें इंस्टीट्यूट में कार्मिकों के उपचार के लिए सीजीएचएस प्रणाली, नर्सिंग कैडर के लिए टाइप 3 आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने को अधिक आवास बनाने आदि बिंदु शामिल हैं।

इसके अलावा, नर्सिंग ऑफिसर की नर्सिंग के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने की सुविधा व राजकीय सेवा में उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक अवकाश सुविधा के बाबत संस्थान अपनी पॉलिसी तय करेगा। लंबित प्रकरणों पर सकारात्मक रुख अपनाने व सौहार्दपूर्वक विमर्श के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स ने एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर(डॉक्टर) मीनू सिंह का आभार प्रकट किया।

जिलाधिकारी ने फसल बीमा योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रमेश कुमार शर्मा/गौरवशाली भारत

बलरामपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक किसानों को आच्छादित किए जाने हेतु जागरूकता रथ को जिलाधिकारी अरविंद सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फसल बीमा जागरूकता रथ द्वारा सभी विकास खंडों में जाकर योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान भाई फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 तक योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने उपनिदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी को योजना का लाभ किसान भाइयों को बताते हुए अधिक से अधिक किसानों को योजना से आच्छादित किए जाने तथा बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति दिलाए जाना सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि ने बताया कि कृषक भाई अपनी निकटतम बैंक शाखा/बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ/कॉमन सर्विस सेंटर सीधे बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन बीमा करा सकते हैं। इस दौरान आधार कार्ड भूमि स्वामित्व दस्तावेज, बैंक पासबुक मोबाइल नंबर साथ में जरूर रखें। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी आरपी राणा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक व बीमा कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

डीएम ने पं0 दिनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय उरमौरा का अक्समिक निरीक्षण किया

सोनभद्र। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने पं0 दिनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय उरमौरा का औचक निरीक्षण किया, इस दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में साफ-सफाई की स्थिति ठीक नहीं पायी। उन्होंने विद्यालय के कक्षों में जाकर बालिकाओं को दी जा रही शिक्षा की स्थिति का जायजा लिया और बालिकाओं से वार्ता की। विद्यालय में उपलब्ध कराया जा रहे भोजन, नास्ता, ड्रेस, बैग, जूता-मोजा आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की, तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि छात्राओं के पास किताब व कापी रखने के लिए बैग उपलब्ध नहीं है और कापी किताब टेबल पर रखकर शिक्षण का कार्य कराया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रभारी प्रधानाचार्या को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये।

छात्राओं को अतिशीघ्र बैग उपलब्ध कराये जाने सुनिश्चित व्यवस्था करने की बात कही। इस दौरान जिलाधिकारी ने लैब का भी निरीक्षण किया तो लैब में प्रेक्टिकल हेतु रखे गये उपकरणों का रख-रखाव बेहतर ढंग नहीं पाया गया और ना ही साफ-सफाई की गयी थी, जिस पर जिलाधिकारी ने लैब में उपकरणों के बेहतर ढंग से रख-रखाव व साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर करने हेतु प्रभारी प्रधानाचार्य को निर्देशित किये। जिलाधिकारी ने छात्राओं के लिए सिलवाकर गये यूनिफार्म के भी निरीक्षण किये, यूनिफार्म निरीक्षण के दौरान यूनिफार्म की सिलाई की क्वालिटी काफी खराब पायी गयी, जिसके सम्बन्ध में प्रभारी प्रधानाचार्या से जानकारी प्राप्त की गयी तो, वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी। इस पर जिलाधिकारी ने यूनिफार्म की सिंलाई ठीक न होने पर सम्बन्धित कांन्ट्रैक्टर के भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दियें। इस मौके पर जिलाधिकारी ने विद्यालय के शौचालय, छात्राओं के हास्टल रूम, किचन रूम व किचन रूम में खाद्य सामग्री के रख-रखाव की स्थिति को देखा, तो किचन रूम में खाद्य सामग्री अव्यवस्थित ढंग से रखी पायी गयी, किचन के निरीक्षण के दौरान छात्राओं हेतु हलुवा बनाये जाने के लिए सूजी को भूना जा रहा था, जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त मामले में जिस स्तर पर लापरवाही बरती गयी हो, सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जाँच में अन्य कार्यो बिंदुओं की भी समीक्षा की तथा इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रभारी प्रधानचार्या को निर्देशित करते हुए कहाकि विद्यालय परिसर में छात्राओं को इण्टरनेट व वाई-फाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। छात्राओं के सुविधा के लिए रैक बनवाये जायें और विद्यालय परिसर में शिक्षा के बेहतर प्रबन्धन हेतु लाईब्रेरी को और बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित किया जाय।

बाल मजदूरी व्यापार है, शिक्षा बच्चों का अधिकार है : सुधांशु शेखर शर्मा

सोनभद्र। सोनभद्र में चोपन ब्लॉक के खण्ड विकास अधिकारी शुभम बरनवाल की अध्यक्षता में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बाल विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला शक्ति केंद्र की संयुक्त बैठक आहूत की गई। बैठक में सबसे पहले पूर्व में की गयी बैठक मे जारी निर्देशो के अनुपालन के बारे मे चर्चा की गई। पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार एजेंडा विषयक प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा बाल श्रम रोकथाम हेतु जागरूकता के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गयी ।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व कन्या सुमंगला योजना में सभी पात्र बच्चों को जोड़ने हेतु सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों से समन्वय बना कर बच्चों का आवेदन कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया जिससे पात्र बच्चों को योजनाओं से

लाभान्वित कराया जा सके। बैठक में संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) तथा स्पॉन्शरशिप योजना, जनपद में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं व बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, बाल तस्करी बाल यौन उत्पीड़न व दत्तक ग्रहण के बारे में समग्र विश्लेषण करते क्रमिक रूप से अवगत कराया।

महिला शक्ति केंद्र से जिला समन्वयक सीमा द्विवेदी ने महिलाओं के लिए संचलित योजनाओं निराश्रित महिला पेंशन, स्वाधार गृह, वन स्टॉप सेंटर, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, विधवा पुत्री विवाह अनुदान आदि योजनाओं के बारे में पूरी परिचर्चा की।

बैठक में बाल विकास परियोजना से मुख्य सेविका सावित्री देवी, ग्राम स्वराज समिति के कार्यकर्ता संजय सिंह,आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता ग्राम प्रधान अनुदेशक, शिक्षा मित्र, पंचायत सहायक उपस्थित रहे।

हिमाचल में पंजाब रोडवेज की बस के नीचे तीन शव बरामद

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में ब्यास में आई बाढ़ में बही पंजाब रोडवेज की बस के नीचे तीन शव बरामद हुए हैं। मंगलवार को प्रशासन की टीम ने बाढ़ में बही बस को बीच नदी ने निकलने का कार्य शुरू किया। नदी के पानी का रुख मोड़कर दो जेसीबी से बस को निकाला जा रहा है। इस दौरान बस के नीचे से दादा व मां-बेटी के शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतकों में परवीन (32), अलवीर (5) पुत्री बहार व अब्दुल (62) शामिल हैं। बस के नीचे कई और शव दबे होने की आशंका है। करीब 24 दिन से एक ही परिवार के 11 लोग लापता थे। इनमें से अभी तीन के शव मिले हैं। नौ और 10 जुलाई को आई प्रलयकारी बाढ़ में कई वाहन बह गए थे। कई वाहनों का अभी तक सुराग भी नहीं मिल पाया है। इस बाढ़ में पंजाब रोडवेज की बस भी बह गई थी। क्लाथ के समीप यह बस एक बड़े पत्थर में फंसी हुई है।

मेवात को नहीं बनने देंगे हिंदुओं का कब्रिस्तान: विहिप

नयी दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र में एक हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए क्रूर हमले के खिलाफ बुधवार दो अगस्त को सम्पूर्ण देश में जिहादी हिंसा एवं क्रूरता के विरोध में धरने प्रदर्शन करने और जिहाद का पुतला दहन करने की घोषणा की है।

विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डा सुरेंद्र जैन ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हरियाणा के मेवात में कल जो भी हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रावण में प्रतिवर्ष किसी भी सोमवार पर मेवात के अंदर भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए महाभारत कालीन पांच मंदिरों में श्रद्धालु जाते हैं।

इस दिन उपद्रवियों द्वारा गोलियां और पत्थर बरसाने तथा आगजनी करके महिलाओं, बच्चों और अन्य भक्तों को शिकार बनाने और उन पर पेट्रोल बम फेंकने की ऐसी घटनाओं से लगने लगा कि पूरा मेवात मानो मिनी पाकिस्तान बन गया है।

डा. जैन ने आरोप लगाया कि इस घटना के जिम्मेदार वे लोग हैं जो इन दंगाइयों को भड़काते हैं उनके भड़काने के कारण से ही, मुहर्रम एवं रामनवमी पर हमले होते हैं।

अन्य कितने लोग बलिदान हुए है उनका पता लगाया जा रहा है, प्रशासन से भी इस बारे में सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। घायलों की चिंता और उनके उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है।

डॉ. जैन ने कहा, यह गंभीर आत्म विश्लेषण का अवसर है कि कल नूह में डायरेक्ट एक्शन की तरह का वातावरण बना था। मैं उन मोलवियों से भी कहना चाहूंगा जो किसी भी बहाने से भड़काने की कोशिश करते हैं, उसका ही यह दुष्परिणाम दिखाई दिया है। यह उचित नहीं है। यह आत्मघाती प्रवृत्ति है।

मणिपुर हिंसा : कानून व्यवस्था ध्वस्त, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को किया तलब

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर हिंसा की स्वतंत्र जांच का आदेश देने की गुहार वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसा लगता है कि मई की शुरुआत से लेकर जुलाई के अंत तक राज्य में कानून-व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था।

शीर्ष अदालत ने कुछ इसी तरह की सख्त टिप्पणियों के साथ मणिपुर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सात अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलील सुनने के बाद ऐसी कई सख्त टिप्पणियां कीं।

पीठ ने जांच पूर्व प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर देते हुए राज्य की हिंसक घटनाओं के विवरण अदालत में सोमवार को उपस्थित होकर खुद देने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया और एक बार फिर कहा कि वह पूर्व न्यायाधीशों की एक जांच समिति गठित कर सकती है।

पीठ ने कहा,हम सभी प्राथमिकियों को सीबीआई को नहीं सौंप सकते। मामलों की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित करना होगा।

शीर्ष अदालत ने राज्य पुलिस की जांच को 'धीमी और सुस्त' पाया और कहा अपराध के घटित होने और पीड़ितों के बयानों को दोबारा दर्ज करने के बीच चूक हुई।

पीठ ने मुआवजे के निर्धारण सहित इसकी छूट पर निर्णय ले सकती है।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से मुर्दाघर में रखे शवों की पहचान स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी मांगी।

पीठ ने यह भी कहा कि वह जाना चाहती है कि हिंसा प्रभावित इलाकों में कितने स्कूल हैं। उनमें कितने छात्र हैं। वहां क्या हालात पढ़ाई के लिए अनुकूल हैं।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा,स्थिति बेहद परेशान करने वाली है। हम ऐसी नाजुक स्थिति में है कि थोड़ा सा धैर्य स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।

अदालत ने दो महिलाओं को नग्न घुमाने और यौन उत्पीड़न के वायरल वीडियो से संबंधित मामले में उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में सरकार से सवाल किया, जिन्होंने कथित तौर पर जीवित बची महिलाओं को भीड़ के हवाले कर दिया था।

नैनीताल में महिला पर्यटक की संदिग्ध मौत

नैनीताल। उत्तराखंड में पर्यटक नगरी के रूप में जाने जाने वाले नैनीताल में एक होटल में महिला पर्यटक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद से महिला का पति फरार है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप्र के मुरादाबाद निवासी मोहम्मद गुलजार अपनी पत्नी इरम खान (32) के साथ नैनीताल घूमने आये थे ?। वह नैनीताल के तल्लीताल स्थित एक होटल में रुके थे। इसी बीच महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का पति फरार हो गया है। पुलिस द्वारा होटल के कमरे का दरवाजा भी खटखटाया गया लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

चुनाव प्रचार में जुटे मोदी को मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं : खड़गे

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और विपक्षी दल उनसे संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं लेकिन इस मुद्दे पर उन्हें बोलने की फुर्सत नहीं है।

खड़गे ने मंगलवार को यहां संसद भवन के नजदीक विजय चौक में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है और भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है जबकि विपक्षी दल इस मुद्दे पर 11 दिन से चर्चा कराने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्रियों ने ऐसी चर्चाओं का जवाब दिया है।

उन्होंने 17 अगस्त 2012 का उदाहरण दिया और कहा कि पूर्वोत्तर के प्रवासियों पर जब हमले हुए थे तो विपक्ष ने इस बारे में सवाल उठाए तो सरकार ने प्रश्नकाल स्थगित किया

और इस मुद्दे पर चर्चा कराके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चर्चा संसद में चर्चा का जवाब दिया था।

उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा पर 65 सांसदों ने नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है। 'इंडिया' गठबंधन मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है जबकि मोदी सरकार नियम 176 के तहत चर्चा की बात कर रही है। दोनों नियमों में बहुत फर्क है। नियम 176 के तहत सिर्फ थोड़े समय के लिए चर्चा की जा सकती है, जबकि नियम 267 के तहत लंबी चर्चा होती है। मणिपुर हिंसा गंभीर विषय है इसलिए विपक्ष द्वारा नियम 267 के तहत लंबी चर्चा की मांग की जा रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा,मोदी सरकार संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपको बड़ी शिक्षा यानी सजा मिलेगी। राज्यसभा अध्यक्ष के मुंह से सरकार यह सब कहलावा रही है।

विपक्ष के बोलने पर सत्ता पक्ष के लोग उठकर चिल्लाते हैं और मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। यह हिटलरशाही है। दस सेकंड में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ये मेरा अपमान है।

उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष को डरा रही है और यही कारण है कि राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल को एक सत्र के लिए निलम्बित किया था और अब दूसरा सत्र चल रहा है फिर भी उनका निलम्बन वापस नहीं किया गया है। ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही है, हिटलरशाही है। नियमों के मुताबिक संजय सिंह ने सवाल उठाया था उनको भी निलम्बित किया गया है लेकिन सरकार को समझ लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन डरने वाला नहीं है।

डरकर भागने के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बना है। इंडिया गठबंधन मोदी सरकार का मुकाबला करेगा और 2024 में मोदी सरकार को हराएगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वह देगा।